CNews सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-240
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सुविचार

शांतिपूर्ण मन ही हमें सच्ची खुशी देता है। इसलिए शांतिपूर्ण मन रखे।

सिटी चीफ

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, गुरुवार 05 दिसम्बर 2024

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

अग्नि और वायु चीते बाड़े से पहुंचे खुले जंगल में, मिली आजादी की हवा

श्योपुर। श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क (केएनपी) में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर दो चीतों, वायु और अग्नि, को जंगल में छोड़ा गया। कूनो के मुख्य वन संरक्षक और डायरेक्टर, लायन प्रोजेक्ट, उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि यह दोनों चीते पूरी तरह स्वस्थ हैं। उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि वायु और अग्नि को कूनो के परोंद वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। यह क्षेत्र अहेरा पर्यटन जोन में आता है, जिससे पर्यटक सफारी के दौरान इन चीतों को देख सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क में इस समय कुल 24 चीते हैं, जिनमें 12 शावक शामिल हैं। पहले ये चीते बाड़ों में रखे गए थे.। चीतों को जंगल में छोड़ने का यह कदम भारत में विलुप्त हो चुकी चीता प्रजाति को दोबारा बसाने के प्रयास का हिस्सा है। करीब 70 साल पहले भारत में शिकार और आवास की कमी के कारण चीते विलुप्त हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को कूनो में छोड़ा था। इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते यहां लाए गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीतों को भारत में बसाने की यह परियोजना दुनिया की पहली अंतरमहाद्वीपीय चीता ट्रांसलोकेशन परियोजना है। दरअसल, कूनो नेशनल पार्क में जन्मे 12 भारतीय चीता शावक अगले डेढ़ से दो साल में पूरी तरह वयस्क हो जाएंगेष 2024 में चीतों के लिए स्थिति 2023 से बेहतर रही, जिसमें 11 नए शावक पैदा हुए और सिर्फ 2 वयस्क और 4 शावकों की मौत हुई। भारत में जन्मे चीते अफ्रीकी चीतों की तुलना में ज्यादा सहज महसूस कर रहे हैं।

छंट गए संशय के बादल, फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर संशय के बादल छंट गए हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा के विधायक दल की बैठक में बुधवार को देवेंद्र फडणवीस को दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक से पहले कोर कमेटी की बैठक में भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। फडणवीस गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने सभी विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। फडणवीस ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए राज्य की जनता का भी आभार जताया। महाराष्ट्र भाजपा के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि महायुति गठबंधन के नेताओं ने बुधवार शाम साढ़े तीन बजे के करीब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। सीएम के साथ ही दो डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। ऐसी चर्चा हैं कि एनसीपी नेता अजित पवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं।

मप्र कैबिनेट की बैठकः सिंहस्थ 2028 को देखते हुए इंदौर-उज्जैन के बीच 2312 करोड़ की सड़क परियोजना को मंजूरी

उज्जैन-इंदौर के बीच एक और फोरलेन हाईवे बनेगा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आगामी सिंहस्थ 2028 को देखते हुए इंदौर-उज्जैन में 2312 करोड़ रुपए से अधिक के सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें उज्जैन सिंहस्थ बायपास के 19.815 किलोमीटर लंबी 4-लेन सड़क का निर्माण, इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग की 48.05 किलोमीटर की 4-लेन सड़क और उज्जैन जिले के इंगोरिया-देपालपुर की 32.60 किलोमीटर 2-लेन सड़क के निर्माण कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं का कुल बजट 2312 करोड़ रुपए है, और यह सभी सड़कें मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से विकसित की जाएंगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई का क्षेत्रफल बढ़ाने और आबकारी नीति निर्धारण के लिए कैबिनेट समिति का गठन शामिल है। कैबिनेट की बैठक में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई के क्षेत्रफल विस्तार को मंजूरी दी गई। अब 442.04 एकड़ भूमि को इस क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे औद्योगिक पार्क का कुल क्षेत्रफल 884 एकड़ हो गया है। इससे ऊर्जा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसके साथ ही, कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण और आवश्यक नीतिगत निर्णयों के लिए एक मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया। इस समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया के साथ ही इस बार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी शामिल किया गया।

उज्जैन सिंहस्थ बायपास पीथमपुर को जोड़ेगा उज्जैन सिंहस्थ बायपास को फोरलेन बनाने का फैसला लिया गया है। यह सड़क पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ेगी। इससे उद्योगों को माल ढुलाई में आसानी होगी। नर्मदापुरम जिले के बाबई में मेगा इंडस्ट्रीयल पार्क बनाया जाएगा। यहां कई तरह के उद्योग स्थापित होंगे। सिंहस्थ महाकुंभ के मद्देनजर उज्जैन-इंदौर की टू लेन सड़क को फोरलेन किया जाएगा। हिंगोरिया-देपालपुर सड़क को भी फोरलेन बनाया जाएगा, जिस पर 239.8 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

25 हजार करोड़ में बनेगा थर्मल पावर प्लांट मप्र सरकार 25 हजार करोड़ रुपए लगाकर थर्मल पावर प्लांट बनाएगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है। दरअसल नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण पार्क के लिए मध्यप्रदेश का चयन हुआ है। केंद्र सरकार इसके लिए 300 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संभागों में निवेश को लेकर बैठकें की थीं। उन्होंने हाल ही में यूके और जर्मनी में भी निवेशकों से बातचीत की। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारा प्रदेश विकास की नई गाथा लिखेगा।

विदेशी निवेशकों ने 71,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए विदेशी निवेशकों ने मध्यप्रदेश में 71,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। ये निवेशक मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा के बाद आगे आए हैं। विजयवर्गीय के मुताबिक विदेश के उद्योगपति मध्यप्रदेश में होने वाले निवेश में पार्टनर भी होंगे। उन्होंने कहा कि मंदी के वातावरण में अगर मध्यप्रदेश में विदेशी निवेश आता है तो औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होगा। आने वाले दिनों में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। यह विदेशी निवेश राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे औद्योगिक क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश विकास के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा।

सोयाबीन-धान खरीदी की समीक्षा करेंगे मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि सीएम यादव ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि सोयाबीन और धान के उपार्जन की समीक्षा मंत्री अपने प्रभार के जिलों में करें। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खरीदी की जाना है। इसके तहत अब तक 77 हजार से अधिक किसानों से 2 लाख 4 हजार मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। रोज 20 हजार मीट्रिक टन की खरीदी औसतन हो रही है।

असम के होटल, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर लगा बैन

नई दिल्ली। असम में बीफ पर बैन लगा दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुधवार को असम मंत्रिमंडल ने राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बीफ पर बैन को लेकर हुए फैसले के बाद असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने पोस्ट किया कि मैं असम कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वह गोमांस पर प्रतिबंध का स्वागत करें या पाकिस्तान में जाकर बस जाएं। दरअसल, सामगुरी सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ था। 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की हार पर सांसद रकीबुल हुसैन ने भाजपा पर बीफ बांटने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को बीजेपी की बैठक के बाद मीडिया से कहा कि वे राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कांग्रेस इसे लिखित में दें।

पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर आतंकी ने की फायरिंग

अमृतसर। अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल में बुधवार को पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर खालिस्तानी आतंकी ने फायरिंग की। सुखबीर बादल गोल्डन टेंपल के गेट पर सेवादार बनकर बैठे थे। डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम को माफी देने को लेकर सिखों की सर्वोच्च अदालत अकाल तख्त ने उन्हें यह सजा दी है। वारदात के वक्त हमलावर ने जैसे ही उन पर गोली चलाई, उसी समय सिविल वर्दी में तैनात उनके सुरक्षाकर्मियों ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया। जिससे गोली गोल्डन टेंपल की दीवार पर जा लगी। इससे सुखबीर बादल बाल-बाल बच गए। इसके बाद हमलावर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। सुखबीर बादल को तुरंत सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। गोल्डन टेंपल के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अमृतसर पुलिस ने गोल्डन टेंपल के पास से संदिग्ध एनआरआई को गिरफ्तार किया है। इस एनआरआई से एक पिस्टल बरामद किया है, जो बिना लाइसेंस का है।

ठंड में खूंखार हो गए कुत्ते.... 7 दिन में 2 नवजातों से बर्बरता; डॉग स्क्वॉड निष्क्रिय

भोपाल सर्दी के दिनों में वाहनों और झाड़ियों के नीचे दुबककर बैठ रहे आवारा कुत्तों को रोटी से ज्यादा मांस की जरूरत रहती है। मांस न मिलने पर इन कुत्तो में विचित्र स्थिति बनती है और हरकत पागलपन जैसी हो जाती है।

यही वजह है कि राजधानी में पिछले 7 दिन में अलग-अलग क्षेत्र में दो नवजात शिशुओं के शवों को लेकर भागे आवारा कुत्ते लेकर भागे। तापमान कम होने या अत्यधिक बढ़ने पर दोनों ही स्थिति में आवारा कुत्ते खूंखार होने लगते हैं। वैसे भी आजकल डस्टबिन या सड़क किनारे गंदगी न होने से आवारा कुत्तों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इससे भी यह कुछ न कुछ खाने के लिए लपकते रहते हैं। नगर निगम का डॉग स्कायड इन दिनों निष्क्रिय है, जिससे दिनभर में 60 से 70 की जगह 10 या 15 कुत्ते भी नहीं पकड़े जा रहे हैं। नगर निगम आयुक्त हुए नाराज नगर निगम आयुक्त ने बुधवार को डॉग स्क्वॉयड की बैठक लेकर नाराजगी व्यक्त की आवारा कुत्तों का पकड़ने की संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि दिसंबर से लेकर जनवरी और फरवरी तक ब्रीडिंग का मौसम रहता है, इसलिए डॉग स्कायड को सक्रिए रहकर एबीसी सेंटर भेजने की संख्या बढ़ाई जाए। रोजाना तीनों एबीसी सेंटर में आवारा कुत्तों को भेजने का लक्ष्य 100 के आसपास होना चाहिए। जबकि इस समय 50 से लेकर 55 ही है।

भोजन के लिए गड्ढा खोद लेते हैं नगर निगम वेटनरी डॉ. बीपी सिंह के अनुसार नवजात शवों को आवारा कुत्तों ने खोजकर गड्ढों से निकाला होगा। क्योंकि मांस खाना, गिलहरी, छिपकली या चूहे पर भी यह लपकते हैं। वैसे यह मौसम इनका ब्रीडिंग का रहता है, इसलिए सर्दी बढ़ते ही यह खूंखार होने लगते हैं, इसलिए सर्दी में इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए।

नगर निगम के आंकड़े गलत समाज सेवी जेपीएस राव के अनुसार, शहर में कहीं भी नगर निगम का डॉग स्क्वॉयड दिखाई नहीं देता है।

राहुल-प्रियंका नहीं जा सके संभल, पुलिस ने काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका

नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बुधवार को उत्तरप्रदेश के संभल नहीं जा सके। यहां उन्हें हिंसा में मारे गए लोगों के परिजन से मिलना था। यूपी पुलिस ने उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया। इससे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर 4 घंटे तक 5 किमी लंबा जाम लगा रहा। हालांकि, राहुल-प्रियंका यहां 3 घंटे ही रुके थे। जाम की वजह से ट्रैफिक में फंसे लोग नाराज हो गए। उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीट दिया। इससे पहले राहुल ने भी अफसरों से बातचीत की और कहा कि मैं पुलिस की गाड़ी में अकेले जाने को तैयार हूं। लेकिन अफसर राजी नहीं हुए। राहुल हाथ में संविधान लेकर कार पर चढ़ गए। मीडिया को संबोधित किया। इसके बाद राहुल-प्रियंका दिल्ली लौट गए। उन्होंने कहा- अब 6 दिसंबर को संभल जाएंगे। संभल में कोर्ट के आदेश पर 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। इस दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें गोली लगने से चार युवकों की मौत हो गई थी।

ओबीसी आरक्षण 27% रिजर्वेशन के अपने ही कानून को नहीं मानती मध्य प्रदेश सरकार

हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

मध्य प्रदेश में होने वाली सरकारी भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को 27 फीसदी आरक्षण नहीं मिलता। बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा-सरकार आखिरकार ओबीसी आरक्षण पर अपना ही कानून क्यों नहीं मानती? वकील ने लंबित याचिकाओं का हवाला देकर सरकार का बचाव किया, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कानून की संवैधानिकता पर जब तक फैसला नहीं आता, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में हुई भतियों में 13 फीसदी पद होल्ड कर दिए गए हैं। इसे लेकर ओबीसी और श्च्ङ्क्ष अभ्यर्थियों ने 300 से ज्यादा याचिकाएं दायर की हैं। कोर्ट ने बुधवार को इन्हीं याचिओं पर सुनवाई करते हुए ओबीसी रिजर्वेशन पर टिप्पणी की है।

एक रहेंगे तो सेफ रहेंगेः बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में लाखों लोग सड़क पर उतरे, नन्हें बच्चों को गोद में लेकर नारेबाजी कर रही थी महिलाएं

इंदौर का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बन गई जन आक्रोश रैली

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में इंदौर में लाखों लोग सड़क पर उतर आए। आरएसएस और भाजपा ने इसे इंदौर का सबसे बड़ा आंदोलन बताया। आंदोलन में लाखों लोगों ने एक सुर में कहा कि इस प्रदर्शन की आवाज दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचना चाहिए ताकि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो सके। इस विरोध प्रदर्शन में इतनी अधिक भीड़ थी कि उसका एक कोना लाल बाग पर था तो दूसरा कोना कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गया था। शहर के व्यापारिक संगठन, संस्थाएं और हजारों संस्थाओं ने इसमें हिस्सा लिया। सुबह 7 बजे से ही इंदौर की सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग नजर आने लगे। कोने कोने से आए इन लोगों ने इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर धरना दिया और ज्ञापन दिया। लोगों ने मांग की है कि इंदौर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। इसमें साधु संत, व्यापारिक संगठन, रहवासी संघ विभिन्न संस्थाएं सामाजिक संगठन सभी शामिल हुए।

भाजपा सहित हिंदू संगठनों ने झोंकी ताकत

इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सभी हिंदू संगठनों ने पूरी ताकत झोंक दी। इससे पहले कांग्रेस ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया था। लगभग एक हफ्ते तक इंदौर में 5000 से अधिक बैठक गली मोहल्ले और कॉलोनी में की गई और उसका परिणाम यह रहा कि यह इंदौर का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बन गया। लाखों की संख्या में लोग एक दिन पहले ही इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके थे।

हर वर्ग और उम्र के लोग शामिल हुए

आंदोलन में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें बड़ी संख्या में कॉलेज के स्टूडेंट, डॉक्टर, वकील, फल सब्जी विक्रेता, छोटे-मोटे व्यापारी और हर उम्र और हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चियों भी इस आंदोलन में शामिल हुई। कई महिलाएं तो अपने साथ में अबोध बच्चों को गोद में लेकर आई और उन्होंने भी बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहां पर हिंदुओं की रक्षा करने के लिए दबाव डाला।

स्वेच्छा से दुकानों को बंद रखा

इंदौर में सभी बाजार सुबह से ही बंद रहे और सभी व्यापारिक संगठनों ने यह कहा है कि वह आधे दिन तक इंदौर में अपनी सभी दुकानों को बंद रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह भी रही की सभी ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद रखा। किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला गया और किसी ने इसके लिए कोई मांग भी नहीं की। इंदौर में किसी भी सड़क से गुजरने पर यह दृश्य साफ तरह से देखा गया कि लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को अपने व्यापार को बंद रखा और बांग्लादेश के ऊपर दबाव डालने में इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया।

बैनर लेकर आई संस्थाएं

अलग-अलग सामाजिक संगठन और संस्थाएं अपने बैनर और पोस्टर के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए ताकि यह बताया जा सके कि वह खुलकर इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं।

रात से ही अलर्ट था पुलिस प्रशासन

बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही सड़कों पर नजर आए। देर रात ही पुलिस और प्रशासन में व्यवस्था कर ली थी कि लाखों लोगों के सड़कों पर उतरने पर किसी भी तरह की कोई घटना न हो इसकी पुख्ता व्यवस्था कर ली जाए। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी स्थिति में कोई भी घटना नहीं होना चाहिए। इंदौर के चप्पे चप्पे पर मंगलवार रात से ही पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई थी। सुबह 6 बजे से ही लाखों लोग सड़कों पर उतरने लगे और पुलिस और प्रशासन ने हर कॉलोनी मोहल्ले में लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया।

भाजपा के बड़े नेता हजारों की भीड़ लेकर पहुंचे

भाजपा नेताओं ने सभी को जिम्मेदारी बांट दी थी और विधायक मालिनी गौड़, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला समेत इंदौर में भाजपा के सभी बड़े नेता अपने-अपने स्तर पर हजारों की संख्या में लोगों को लेकर आए। इसके लिए बड़ी संख्या में स्कूलों की बसों का अधिग्रहण किया गया और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को भी लोगों के आने-जाने में लगाया गया।

...तो इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शन में शामिल हुए सभी संगठनों ने एक सुर में कहा कि यदि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और भारत सरकार पर दबाव डाला जाएगा कि वह तुरंत बांग्लादेश के ऊपर सख्त कार्रवाई करे। लोगों ने कहा कि इस आंदोलन को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जाए क्योंकि यह बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं मानवता की रक्षा की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ-साथ जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म समेत सभी धर्म पर अत्याचार हो रहा है और यदि इसी तरह मानवता पर अत्याचार होता रहा तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। मानवता की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होना होगा और एक साथ आवाज उठाना होगी।

हिंदुओं पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे

रैली में शामिल होने पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, बांग्लादेश में हो रहे हिदुओं पर अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए अहिल्यानगरी में जनसैलाब सड़कों पर उतरा है। विधायक रमेश मेंदोला ने कहा, धर्म जीवन का आधार है। इसी आधार पर मानवता टिकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, वहां की सरकार के खिलाफ भारत का हिंदू सड़क पर उतरा है।

10 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू, गड्ढों और स्पीड ब्रेकर पर भी झटके नहीं लगेंगे

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में बुधवार से यात्रियों के लिए 10 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर दी गईं। इसके साथ ही शहर में इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या बढ़कर 80 हो गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड परिसर से 35 सीटर इलेक्ट्रिक-एसी बसों का शुभारंभ किया। इन बसों का संचालन सिटी बस मार्ग क्र. एम-6 पर होगा, जो राजवाड़ा चौक से तेजाजी नगर चौराहे (भंवरकुआ चौराहे के रास्ते) तक चलेगा। यह मार्ग कुल 10.5 किमी लंबा है और इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 19 बस स्टॉप होंगे। शुभारंभ के इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि शहर में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने और एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी 50 नई सिटी बसों में से 10 बसों का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि आवश्यकता के अनुसार धीरे-धीरे इन बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इंदौर में बसें चैन्नई से आई है। बस की खासियत यह है कि गड्ढों और स्पीड ब्रेकर पर भी इसमें झटके नहीं लगेंगे। इसके सस्पेंशन वॉल्वो बस की तरह एयर सस्पेंशन हैं। सीटें गद्देदार हैं। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि ई-बस में डबल चार्जर सिस्टम है, जिससे बस का चार्जिंग समय

आधा हो जाता है। सिंगल चार्जर से अगर बस 6 घंटे में चार्ज होती है, तो डबल चार्जर से यह 3 घंटे में चार्ज हो जाएगी। बस एक बार चार्ज होने पर 300 से 350 किमी तक चलेगी। अधिकारियों के अनुसार, बस की सबसे खास बात यह है कि इसकी सीटिंग अन्य बसों की तुलना में ज्यादा आरामदायक है और यह बिना आवाज के चलती है। इसका पिकअप और ब्रेक कंट्रोल सामान्य बसों से बेहतर है। नई इलेक्ट्रिक बसें मौजूदा बसों की तुलना में ज्यादा आरामदायक हैं और कई आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इनमें एसी, जीपीएस, फायर अलार्म, सीसीटीवी कैमरे, ऑनबोर्ड यूनिट जैसी सुविधाएं होंगी, जो यात्रा को सुरक्षित बनाएंगी। इन बसों को चार्ज करने के लिए आईसीटीएसएल और राजीव गांधी डिपो के साथ ही शहर में नए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे।

संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर जिले में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल, इसे बेचने और स्टॉक करने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसके आदेश जारी किए हैं। मकर संक्रांत का त्योहार करीब है। त्योहार पर लोग पतंगबाजी करते हैं। कुछ लोग चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हैं। इससे दुर्घटनाएं होती हैं। मांझे से घायल होने और यहां तक के मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं। इसी वजह से कलेक्टर ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझे को प्लास्टिक का मांझा या डोर भी कहते हैं। चाइनीज मांझा अन्य मांझों की तरह धागे से नहीं बनता। यह नायलॉन और एक मैटेलिक पाउडर को मिलाकर बनाया जाता है। यह प्लास्टिक जैसा लगता है और स्ट्रेचेबल होता है। ऐसे में जब इसे खींचते हैं, तो यह टूटने के बजाय बढ़ जाता है। यह मांझा ब्लेड

की तरह पैना होता है। बता दें कि खंडवा जिले में चाइनीज मांझे से एक रेलवे कर्मचारी की गर्दन कटने का मामला सामने आया है। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मचारी माल गोडाउन क्षेत्र से ड्यूटी कर घर लौट रहा था। तभी अचानक चाइनीज मांझा गाले में फंस गया, जिस से रेलवे कर्मचारी की गर्दन काट गई। कर्मचारी ने तत्काल इसकी सूचना अपने साथ ड्यूटी कर रहे लोगों को फोन पर दी। जिसके बाद घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, फिलहाल घायल युवक की हालत में सुधार है। वहीं इस घटना के बाद यह सवाल उठ रहा है कि जब चाइनीज मांझा पूरी तरह से प्रतिबंध है, तो बाजारों में इसकी बिक्री कैसे हो रही है

सरकारी विभागों के बिजली खपत में 20% की कमी लाई जाएगी

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। स्वच्छता के बाद अब इंदौर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के क्षेत्र में भी अव्वल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसको देखते हुए इंदौर शहर में क्लाइमेट मिशन प्रारंभ किया गया है। मिशन का पहला चरण 100 दिन का रहेगा।

यह दिसंबर माह से शुरू होकर मार्च तक चलेगा। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिले के शासकीय विभागों के कार्यालय भी सहभागी बनेंगे। इन कार्यालयों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बिजली खपत में 20त्न की कमी लाई जाएगी। यह जानकारी सोमवार

को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। बैठक में मिशन से जुड़े सोलर मेन चेतन सिंह सोलंकी ने मिशन के विभिन्न बिन्दुओं, उद्देश्यों और गतिविधियों के बारे में बताया। बैठक में नगर निगम, स्मार्ट सिटी, आईडीए सहित अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि समय को देखते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कारगर प्रयासों की जरूरत है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी सरकारी विभाग सहभागी बने। वे यह प्रयास करें कि अपने-अपने कार्यालयों में बिजली की खपत कम से कम 20त्न कम हो। अभियान में ऊर्जा साक्षरता, बिजली की खपत में कमी लाने, व्यवहार में बदलाव लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

देखने को मिला एक पैसे से 10 रुपए तक के सिक्कों के एल्बम का प्रदर्शन

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर फिलेटलिक सोसाइटी एवं इंदौर न्यूमिस्मैटिक सोसायटी की यादगार मासिक बैठक 1 दिसंबर को आयोजित की गई। सभा के सभापति आलोक खादीवाला रहे। इस अवसर पर सुरेंद्र मुल्ये द्वारा बिजनेस रिप्लाई मेल का प्रदर्शन एवं उन पर विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। सभा में द्वारका प्रसाद अग्रवाल द्वारा पोस्ट इंडियन कॉइन एक पैसे से 10 रुपए तक के सिक्कों के एल्बम का प्रदर्शन एवं उस पर विस्तृत जानकारी दी। मुख्य संरक्षक गिरीश शर्मा आदित्य द्वारा सिक्कों की जानकारी एवं आगामी फरवरी माह की एग्जीबिशन के बारे में बताया गया। आलोक खादीवाल, द्वारका प्रसाद अग्रवाल, कपिल नीमा के सौजन्य से उपहार का वितरण किया। नरेंद्र अग्रवाल द्वारा सभा प्रारंभ की

घोषणा की गई। सुरेश भागचंदानी द्वारा अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। डॉ. रवींद्र नारायण पहलवान (अध्यक्ष) ने उद्बोधन दिया। सभा का संचालन राजेश शाह (कार्यकारी अध्यक्ष) ने किया। आभार सुरेंद्र मुल्ये (मानद सचिव) ने माना।

नगर निगम की पहल... इंदौर में देश के पहले शौचालय पॉडकॉस्ट की शुरुआत

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के जोन 9 के वार्ड 47 स्थित नेहरू पार्क के सुलभ शौचालय परिसर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां शौचालय को पॉडकास्ट स्टूडियो में बदल दिया गया। दरअसल, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे आदत में शामिल करने के उद्देश्य से इंदौर नगर निगम ने यह अनूठा प्रयोग किया है। शौचालय के बाहर पॉडकॉस्ट किया गया, जिसमें नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बात की। इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश के पहले शौचालय पॉडकास्ट की शुरुआत की है। शौचालय को पॉडकास्ट स्टूडियों में बदलकर इस अभिनव पहल को लागू किया है। इस स्वच्छ शौचालय पॉडकास्ट का उद्देश्य स्वच्छता को लेकर एक नई सोच विकसित करना और इसे मनोरंजक व प्रभावी तरीके से पेश करना है। इस पहल की शुरुआत नेहरू पार्क स्थित सुलभ शौचालय परिसर में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने की। कार्यक्रम का संचालन आरजे साक्षी ने किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय झोनल अधिकारी पीएस कुशवाह, उपयंत्री श्रीराम गुप्ता और एनजीओ संस्था एचएमएस के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। उन्होंने स्वच्छता के महत्व, शौचालय की उपयोगिता और अपने अनुभव साझा किए। इंदौर नगर निगम ने इस पहल के जरिये स्वच्छता को मनोरंजन से जोड़ते हुए लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इंदौर पहले ही एक लाख सेल्फियों का रिकॉर्ड बनाकर देशभर में चर्चित हो चुका है। अब यह पॉडकास्ट पहल लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और इसमें उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। आयुक्त वर्मा ने कहा कि इंदौर हमेशा स्वच्छता में अग्रणी रहा है। यह पहल न केवल जागरूकता फैलाने का जरिया है, बल्कि नई पीढ़ी को स्वच्छता की आदत डालने की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है।

भोपाल में भील डकैत गिरोह सक्रिय, 8 माह में 4 वारदातें,एक बदमाश पकड़ाया

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। राजधानी भोपाल में इन दोनों भील डकैतों का 5 सदस्यीय गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह आउटर कालोनियों के सूने मकानों को अपना निशाना बनाता है। पिछले 8 महीने के भीतर गिरोह ने 4 वारदातों को अंजाम दिया है। कटारा हिल्स पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह भोपाल के अलावा रीवा, जबलपुर, कटनी तथा गुजरात के कई जिलों में भी चोरी, लूटपाट और नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। फरार हुए गिरोह के साथियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। जानकारी के अनुसार करीब एक सप्ताह पहले सेज सनसिटी कटारा हिल्स में रहने वाली एक महिला के घर बदमाशों ने धावा बोला और हजारों

रुपये के जेवरात तथा अन्य सामान चोरी कर ले गए थे। इस मामले की रिपोर्ट महिला के भाई बाग मुंगालिया निवासी ललित शर्मा ने दर्ज कराई थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने पर पांच संदेही बदमाश दिखाई दिए थे, जिनकी धरपकड़ के लिए विशेष टीम बनाई गई थी। यह टीम रात के समय इलाके की सर्चिंग कर रही थी, तभी पता चला कि पांच व्यक्ति चोरी के उद्देश्य से प्राईड सिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। यह भी बताया गया है कि उक्त व्यक्तियों का हुलिया सनसिटी कालोनी में चोरी करने वालों से मिलता-जुलता है। बाइक के साथ एक बदमाश पकड़ाया है।

अंधेरे का फायदा उठाकर भागे चार बदमाश

कटारा हिल्स थाना प्रभारी बिजेंद्र निगम ने बताया कि टीम जब मौके पर पहुंची तो पांच व्यक्ति दिखाई दिए। घेराबंदी के दौरान वह बाइक स्टार्ट कर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने एक बदमाश को दबोच लिया, जबकि उसके चार साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पूछताछ के दौरान पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम करन बघेल उर्फ रण सिंह (22) निवासी ग्राम गुराडिया तहसील कुक्षी, थाना टाण्डा जिला धार बताया। उसके पास मिली बाइक चोरी की निकली। मौके से फरार हुए बदमाशों के नाम उसने गुड्डू उर्फ गजेन्द्र, सुखराम और संजय बसुनिया सभी निवासी टाण्डा जिला धार बताए।

महिला को बंधक बनाकर की वारदात

पकड़े आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सेज सनसिटी कालोनी में वारदात करना स्वीकार किया। इसके अलावा उसने कटारा हिल्स की प्राईड सिटी में एक महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देना बताया। साथ ही बायपास मार्ग से लगी दो अन्य कालोयिनों के सूने मकानों में वारदात करना स्वीकार किया। बदमाश यहां से लाखों रुपये कीमत के जेवरात और अन्या सामान चोरी कर ले गए थे।

इसके साथ ही गिरोह ने रीवा, कटनी में नकबजनी, जबलपुर स्थित जैन मंदिर में लूटपाट, अलीराजपुर में लूटपाट का प्रयास और गुजरात के पोरबंदर में नकबजनी की घटना को अंजाम देना बताया। इस प्रकार देते थे घटना को अंजाम थाना प्रभारी बिजेंद्र निगम ने बताया कि यह गिरोह शहर की आउटर कालोनियों के सूने मकानों को निशाना बनाता था, ताकि वारदात को बाद उन्हें भागने में आसानी हो। बदमाश शाम के समय कालोनियों के आसपास खेतों और मेड़ों पर सो जाया करता है। रात दो बजे उठकर वह मकानों में वारदात को अंजाम देकर वापस अपने घर धार लौट जाता था। गिरोह के फरार चार अन्य साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके मिलने पर शहर में हुई कई अन्य वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है।

न शादियों में होगा तंदूर, न मिलेगी तंदूरी रोटी...

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। राजधानी भोपाल में इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं। ठंड के शुरुआती दिनों में ही न्यूनतम पारा 8.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस बीच बढ़ते एयर पॉल्यूशन ने प्रशासन सहित लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। शहर की आबो हवा को बेहतर बनाए रखने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है। नगर निगम ने इस साल अलाव की व्यवस्था नहीं की है। निगम प्रशासन ने शादी पार्टियों में भी तंदूर पर बैन लगा दिया गया है। यानी, इस साल वेडिंग सीजन में तंदूरी खाना-तंदूरी रोटी नहीं मिलेगी। साथ ही, कचरा या लकड़ियां जलाने पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि देश में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन, तंदूर पर रोक होने के चलते इस बार मेहमाननवाजी में तंदूरी खाना नहीं होगा। जिनके घर में शादी है उनका कहना है कि एयर पॉल्यूशन के चलते अगर रोक लगाई गई है तो हम तंदूर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन, सिर्फ तंदूर और अलाव से ही शहर में प्रदूषण नहीं बढ़ रहा। शहर की सड़कों पर धूल उड़ती रहती है, बिना पीयूसी के चल रहे वाहन भी पॉल्यूशन का बड़ा कारण हैं। इन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।

रैन बसेरों के केयरटेकर चिंता में

लोगों का कहना है कि सरकार को रैन बसेरे और फुटपाथ पर रह रहे लोगों के बारे में भी चिंता करना चाहिए. क्योंकि, हर साल नगर निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था होती थी। यह व्यवस्था अब नहीं होगी। रैन बसेरों के केयरटेकर

का कहना है कि इस साल लोगों के लिए सिर्फ रजाई, कम्बल, गद्दों के इंतजाम हैं। इसी के सहारे लोगों को अपनी रात गुजारनी होगी। निगम प्रशासन की ओर से अलाव का कोई वैकल्पिक इंतजाम अब तक नहीं किया गया है।

400 के पास पहुंच गया था एक्यूआई

ठंड के सीजन की शुरुआत में ही दिवाली के समय शहर का एक्यूआई इंडेक्स 400 के पास पहुंच गया था। यह बेहद खराब स्थिति में आता है।

कई हफ्तों तक एक्यूआई 300 के पार भी रहा। इसके चलते अब निगम प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े हैं। पर अलाव का कोई विकल्प इंतजाम न होना इन सर्दियों में गरीबों और फुटपाथ रहने वाले बेसहाराओं पर भारी मुसीबत बनकर टूटेगा।

भोपाल के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश के पांच बड़े जिलों की बात करें तो राजधानी भोपाल शहर की हवा फिर खराब स्तर पर पहुंच गई है। यहां के ईदगाह हिल्स इलाके में एक्यूआई लेवल 299 दर्ज किया गया। अन्य बड़े जिलों की बात करें तो ग्वालियर में 259, जबलपुर में 158, उज्जैन में 107 और इंदौर में 104 एक्यूआई लेवल दर्ज हुआ है। राजधानी भोपाल के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। यहां शहर के आसपास के खेतों में पराली जलाना और शहर की जर्र सड़कों पर उड़ने वाली धूल से हवा प्रदूषित हो रही है। शहर के लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

पीडब्ल्यूडी के कामों में नई तकनीकी को लेकर हुआ मंथन

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। हमारी जवाबदेही ठेकेदारों के लिए नहीं है। हमारी जिम्मेदारी अपने काम को उत्कृष्ट रूप में करने की है। हम जो भी निर्माण करें वह ऐसा हो कि हम परिचितों और परिजनों के साथ गर्व के साथ शेयर कर सकें। हमें अपने काम से अपनी इमेज बदलना है और जो नकारापन हमको लेकर समाज में मौजूद है, उसे ठीक करना है।

लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने यह बात बुधवार को प्रशासन अकादमी में विभाग के इंजीनियर्स को संबोधित करते हुए कहीं। सिंह ने कहा कि अगर नवाचार के किसी काम में कोई गड़बड़ होने की संभावना है तो उसे मीडिया और जनता के बीच पहले से बताएं ताकि गड़बड़ होने पर किसी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। मंत्री तो आते-जाते रहेंगे पर आपको विभाग में रहना है, इसलिए आपकी पहचान आपके काम से ही है। मंत्री सिंह ने कहा कि जो नए इंजीनियर आ रहे हैं, उनसे मुख्य अभियंता संवाद करें और उन्हें पुरानी तकनीक के बारे में बताने के साथ उनके नवाचारों और विचारों को समझें।

डॉक्टर बनना था, नेता बन गया

मंत्री सिंह ने कार्यशाला में अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन अचानक छात्र राजनीति में आ गया। इसके बाद जब पीएमटी की परीक्षा देने के लिए गया तो यह लग रहा था कि कहीं धोखे से पास न हो जाऊं। मेरी नियति मुझे यहां ले आई। सिंह ने कहा कि पहले के दौर में जब स्टूडेंट पास होते थे तो फर्स्ट क्लास वाले छात्रों की संख्या एक पेज में होती थी और सेंकेंड क्लास वाले दो से तीन पेज में रहते थे तथा थर्ड क्लास वाले स्टूडेंट्स के नाम तीन से चार पेज में होते थे।

नई तकनीकी पर कार्यशाला में हुआ मंथन

इस कार्यशाला में लोक निर्माण विभाग के विभागीय कार्यों में नई तकनीकी को शामिल करने और विकास परियोजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मंथन हुआ। पहले सत्र में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और युवा इंजीनियर शामिल हुए।

आईआरसी सेमिनार की रिपोर्ट पर चर्चा

इस वर्कशॉप में 19 और 20 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) के सेमिनार और रायपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हुई चचाओं को साझा किया गया। भवन विकास निगम और लोक निर्माण विभाग के भारतीय प्रबंध संस्थान (ककट) इंदौर से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 26 युवा इंजीनियरों ने कार्यशाला में अपनी रिपोर्ट पेश की। इन रिपोर्ट्स में प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान और उसे व्यावहारिक रूप से लागू करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई।

चार समूहों के माध्यम से आई रिपोर्ट

कार्यशाला को प्रभावी बनाने के लिए 4 समूहों का गठन किया गया। हर समूह निर्माण क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों पर चर्चा कर रिजल्ट बेस्ड ठोस कार्य योजना तैयार कराई जा रही है। कार्य योजना लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के समक्ष पेश की गई।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन में जुटे एक लाख लोग

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। भोपाल में बुधवार को सकल हिंदू समाज के आह्वान पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन हुआ। भारत माता चौराहा पर दोपहर 2 बजे से लोग एकत्रित हुए। इसके बाद 2 किमी लंबी रैली में एक लाख से अधिक लोग नारेबाजी करते हुए रोशनपुरा चौराहे पहुंचे। यहां कमिश्नर संजीव सिंह और जिपं सीईओ ऋतुराज सिंह को ज्ञापन सौंप कर रैली का समापन किया गया। प्रदर्शन को व्यापारियों का भी समर्थन मिला। भोपाल के बाजार आधे दिन तक बंद रहें। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने अनाज की खरीदी नहीं की। भोपाल का थोक दवा बाजार भी पूरी तरह से बंद है। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ ने बताया, थोक दवा दुकानें नहीं खुली। मेडिकल खुले रखे गए। भोपाल में टीला जमालपुरा में मार्केट बंद करने पहुंचे भाजपा कार्यकताओं से कुछ लोगों की झड़प हो गई। दोनों पक्ष ने एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए गए। प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, बीजेपी जिलाध्यक्ष समित पचौरी, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, सुरेश पचौरी सहित हजारों के तादाद में लोग रहें।

दो आईपीएस का तबादला, उपेंद्र कुमार जैन अब डीजी ईओडब्ल्यू होंगे

अजय शर्मा को एमपी पुलिस हाउसिंग का अध्यक्ष बनाया

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। कैलाश मकवाना के मप्र का नया पुलिस महानिदेशक बनते ही राज्य शासन ने डीजी पद के दावेदार रहे अफसरों के बुधवार को तबादला आदेश जारी कर दिए। इसमें 1989 बैच के आईपीएस और वर्तमान में डीजी ईओडब्ल्यू अजय कुमार शर्मा को मप्र पुलिस आवास और अधोसंरचना विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह 1991 बैच के आईपीएस एमपी पुलिस आवास और अधोसंरचना विकास निगम के प्रबंध संचालक उपेंद्र कुमार जैन (स्पेशल डीजी) को डीजी ईओडब्ल्यू के पद पर पदस्थ किया गया है।

प्रदेश के कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों और अन्य आईपीएस अफसरों के भी तबादले जल्द होंगे। यह तबादले नवम्बर में ही होना थे। लेकिन नए डीजीपी के चयन के चलते तबादलों की कार्यवाही को रोक दिया गया था।

सीएम डॉ मोहन यादव ने नए डीजीपी के चयन के बाद पुलिस अफसरों के तबादले पर सहमति दी थी। अब जबकि सीएम यादव विदेश दौरे से लौट आए हैं और नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने चार्ज लेने के बाद कामकाज शुरू कर दिया है, तो जल्दी ही कुछ जिलों के एसपी, रेंज आईजी के साथ सीनियर आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर आदेश जारी किए जाएंगे। मंत्रालय अफसरों के मुताबिक तबादला लिस्ट तैयार है, इसमें नए डीजीपी के साथ चर्चा के बाद बदलाव कर आदेश किए जाना है।

भोपाल की वाजपेयी नगर कॉलोनी में मिला नवजात का सिर, धड़ कुत्ते खा गए

भोपाल। भोपाल में नवजात का सिर मिला है। धड़ कुत्ते खा गए। पुलिस को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद नवजात के बचे हुए सिर को पुलिस ने हमीदिया अस्पताल की मॉच्युर्री में रखवा दिया । बुधवार को पोस्टमॉर्टम कराया गया। मामला शाहजहांनाबाद थाना इलाके की वाजपेयी नगर झुग्गी बस्ती का है। शाहजहांनाबाद थाना प्रभारी यूपीएस चौहान ने बताया कि दोपहर 1 बजे नवजात का शव पड़े होने की जानकारी मिली थी। लोगों ने बताया था कि वाजपेयी नगर स्थित मल्टी के पास झाड़ियों में शव को कुत्ते नोच रहे हैं। थाना प्रभारी के मुताबिक, शव के नीचे का हिस्सा यानी धड़ कुत्तों ने खा लिया है। इसलिए नवजात लड़का है या लड़की, यह पोस्टमॉर्टम के बाद ही कहा जा सकता है। जांच शुरू कर दी गई है। आसपास के लोगों और अस्पतालों में पता लगाया जा रहा है कि हाल ही में किसकी डिलीवरी हुई है। पुलिस के मुताबिक, वाजपेयी नगर कॉलोनी के लोगों ने बताया कि बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे।

हमीदिया के आउटसोर्स कर्मचारी आज करेंगे हड़ताल, 2 माह से नहीं मिला वेतन

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में 1000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं लेकिन उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह गांधी मेडिकल कॉलेज के पास पर्याप्त बजट नहीं होना बताया जाता है। समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण हमीदिया अस्पताल के तकरीबन एक हजार से अधिक कर्मचारी गुरुवार से कम बंद हड़ताल पर जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से सभी कर्मचारी अस्पताल के सामने आमरण पर बैठेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी की हड़ताल पर जाने से हमीदिया अस्पताल में आने वाले हजारों मरीजों की परेशानी बढ़ जाएगी। यहां पर आउटसोर्स कर्मचारी वार्ड बॉय,

टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी और कंप्यूटर सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं संभाल रहे हैं। ऐसे में अगर ये हड़ताल पर जाते हैं तो मरीजों की परेशानी बढ़ जाएगी। एक कर्मचारी ने बताया कि पहले यह हड़ताल बुधवार को होने वाली थी लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर चल रहे अत्याचार के कारण भोपाल में दूसरा आंदोलन चल रहा है, इस वजह से हमने अपने आंदोलन को एक दिन तक टाल दिया है। अब यह गुरुवार को सुबह से शुरू होगा। गौरतलब है कि दीपावली के समय आउटसोर्स कर्मचारी ने हड़ताल किया था तब जाकर उन्हें 3 महीने का वेतन दिया गया था।अब दो महीने का समय बीत गया और उन्हें दोबारा वेतन नहीं दिया गया है। इसी कारण वे दोबारा हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।

दिवाली के बाद अब तक नहीं मिला वेतन

हमीदिया अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी का कहना है कि वैसे भी हमें कम वेतन मिलता है और समय पर नहीं मिलता जिस वजह से घर चलना मुश्किल हो रहा है।कर्मचारियों को कहना है कि इस बार लिखित में आदेश लेंगे कि हर महीने वेतन मिलेगा, तभी पीछे हटेंगे। हमीदिया अस्पताल में वार्ड बॉय, टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी और कंप्यूटर सहित अन्य स्वास्थ्य सेवक एक साथ हड़ताल पर जा रहे हैं। इनका कहना है कि दिवाली के समय तीन महीने का वेतन बड़ी मुश्किल से दिया गया। अब फिर दो माह का वेतन उलझा दिया गया है। जिससे परिवारों में आर्थिक संकट गहरा गया है। इन कर्मचारियों ने गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. कविता एन सिंह को भी यह समस्या बताई जा चुकी है। जितना वेतन मिल रहा है। उसमें परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इतना कम पैसा देने के बाद भी समय पर भुगतान न करना कर्मचारियों के साथ नैसर्गिक न्याय नहीं है। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि गुरुवार से कोई काम नहीं करेंगे।

कंपनी का 6 महीने से नहीं हुआ भुगतान

हमीदिया अस्पताल में आउटसोर्स का काम करने वाली एलाइजा कंपनी का पिछले 6 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। यही वजह है कि कंपनी कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रही है। एलिसा कंपनी के मैनेजर अंकित सिंह का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के लिए कंपनी लगातार प्रयास कर रही है। जीएमसी डीन से लगातार चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि जब कॉलेज प्रशासन हमें पैसा देगा, तभी हम कर्मचारियों के खातों में डालेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारी हड़ताल न करें और मरीजों की परेशानी ना बढ़े।

सम्पादकीय

खैरात बांटने के बजाय संरचनात्मक सुधार करें राज्य सरकारें

यह टकसाली सत्य है कि राज्य सरकारें बढ़ते कर्ज और घटते राजस्व के चलते वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। यह वक्त की दरकार है कि राज्य सरकारें अपना ध्यान खैरात बांटने के बजाय संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित करें। दरअसल, राज्यों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए राजकोषीय विवेक, कुशल कर संग्रह और तार्किक सब्सिडी समय की मांग है। आने वाले समय में पंजाब और हिमाचल की तरह आर्थिक संकट से जूझ सकते हैं। इसमें दो राय नहीं।

वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह राजनीतिक दल और उनके नेता वादों की बरसात करते हैं, उसे नाम दिया गया है रेवड़ी कल्चर। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इस रेवड़ी कल्चर को देश के लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में इस तरह 'मुफ्त बांटने' की योजनाएं आम बात है। महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले मध्यप्रदेश की तर्ज पर लाडकी बहिण योजना शुरू की गई। विरोध करने वाले इन्हें 'फ्रीबीज' और रेवड़ी कल्चर कहते हैं तो समर्थन वाले इन्हें 'कल्याणकारी योजनाएं' बताते हैं। विरोध करने वालों का अकसर कहना होता है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, कर्जा बढ़ेगा और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं ऐसी योजनाएं लाने वाले कहते हैं कि इसका मकसद गरीब जनता को महंगाई से राहत दिलाना है। खास बात यह है कि एक पार्टी इस तरह की योजना को एक राज्य में रेवड़ी कल्चर कहती है, वही दूसरे राज्य में उसे कल्याणकारी योजना कहकर लागू कर रही होती है। सत्ता हासिल करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अख्तियार कर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की कीमत अब पंजाब और हिमाचल चुका रहे हैं। दोनों राज्य फिलहाल गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह आर्थिक संकट चुनावी अभियानों के दौरान किए गए लोकलुभावन वादों के चलते ही उत्पन्न हुआ है। जिसके कारण पिछले दिनों हिमाचल में कर्मचारियों को वेतन व सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देने में व्यवधान देखा गया। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने मतदाताओं को तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। सत्ता में आने पर राज्य सरकार ने अपने वादे को अमली जामा पहनाया। इसके चलते चालू वित्त वर्ष के लिए बीस हजार करोड़ से अधिक सब्सिडी बिल आया है। इसी तरह कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया। यह तय था कि इस घोषणा से राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस आसन्न संकट को महसूस करते ही विगत में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना से हाथ खींच लिया था। लेकिन अब हिमाचल सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को पुनर्जीवित करने से, पहले से ही संकटग्रस्त सरकारी खजाने पर एक बड़ा बोझ और बढ़ गया है। वहीं पंजाब में सब्सिडी भुगतान में देरी से पंजाब की स्थिति और खराब हो गई है। लंबित बिल साढ़े चार हजार करोड़ से अधिक हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब स्टेट पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी पीएसपीसीएल की बिल संग्रह दक्षता में भारी गिरावट आई है। दरअसल, पीएसपीसीएल पहले ही ट्रांसमिशन घाटे में वृद्धि के संकट से जूझ रहा है। हालांकि, पंजाब स्टेट पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिजली के बिल के बकायादारों और कतिपय सरकारी विभागों से बकाया धनराशि वसूलने से राजस्व बढ़ाने के प्रयासों में कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिसकी कीमत कालांतर राज्य की आर्थिकी को ही चुकानी होगी। निश्चित तौर पर पंजाब को मुफ्त की बिजली देने से उत्पन्न संकट से जल्दी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आते। राज्य फिलहाल उधार हासिल करने की सीमा के करीब पहुंच गया है। इसके चलते मुफ्त बिजली योजना चलती रह सकेगी, इसमें संदेह है। कमोबेश हिमाचल प्रदेश भी ऐसे ही संकट से दो चार है। राज्य की वित्तीय बदहाली इस बात की गवाह है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली ने राज्य के वित्तीय दायित्वों को बढ़ा दिया है। इसके चलते वेतन और पेंशन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये मासिक रूप से दो हजार करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। जो वित्तीय दिक्कतों की अंतहीन शृंखला को जन्म दे रही है।

यौन हिंसा को लेकर लगातार संघर्ष कर रही छात्राएं

बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए नौ साल पहले पॉक्सो कानून बनाया गया था। सवाल यह है कि क्या कानून अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा है? 2016 से 2020 तक (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट किए गए बाल यौन शोषण के मामलों की संख्या 2016 में 36321 से बढकर 2020 में 47 हजार से अधिक हो गई। यह 31 प्रतिशत की वृद्धि है। विशेषज्ञों के अनुसार यह संख्या भी हिमखंड का सिरा मात्र है। एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में से सिर्फ 36 फीसदी ही पॉक्सो के तहत दर्ज होते हैं।

नवंबर 2024 में दिल्ली में शाहदरा के आनंद विहार इलाके में एक स्कूल बस में एक स्कूली छात्रा के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। स्कूल छात्राओं का इस प्रकार का शोषण देश के अनेक राज्यों में लगातार देखने को मिल रहा है। इन ज्यादातर मामलों में आरोपी शिक्षा संस्थानों से जुड़े लोग ही होते हैं। यह एक सामाजिक चिंता का कारण है। ऐसे सभी मामले दूरदराज के छोटे गांवों से लेकर जाने-माने विश्वविद्यालयों तक के हैं, जहां यौन हिंसा को लेकर लड़कियां लगातार संघर्ष कर रही हैं और कई बार तो उनके स्कूल या कॉलेज छोड़ने तक की नौबत भी आ जाती है। लैंगिक भेदभाव के अलावा इस तथाकथित आधुनिक समाज में यौन शोषण एक बड़ा कारण भी है जिससे लड़कियां शिक्षा से दूर हो जाती हैं या उनके अभिभावकों द्वारा दूर कर दी जाती हैं।

अकसर शिक्षा और रोजगार के लिए जारी रिपोर्ट्स में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखकर सभी खुद को शाबाशी देने लगते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अभी भी समाज के कई हिस्सों में लड़कियों को अपनी बुनियादी शिक्षा और विकास के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के मुताबिक लगभग पांच में से एक लडकी अभी भी निम्न-माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही है। लगभग 10 में से चार लड़कियां आज भी उच्च-माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही हैं। कुछ क्षेत्रों में तो संख्या और भी निराशाजनक है। यह पूरी दुनिया का हाल है। अपने यहां के हालात भी कुछ ऐसे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यहां प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद लगभग 65 फीसदी लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया था।

ये आंकड़े शिक्षा मंत्रालय ने अपनी पहली 'ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति' रिपोर्ट में बताए हैं। हालांकि इस पढ़ाई छोड़ने के पीछे यौन हिंसा के अलावा और भी कई बड़े कारण हैं, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले तीन सालों में बच्चों के खिलाफ 418385 अपराध दर्ज किए गए। इनमें पॉक्सो एक्ट के तहत करीब 134383 मामले दर्ज हुए। पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस) जैसे कड़े कानून के बावजूद भारत में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनमें साल दर साल इजाफा हो रहा है। महानगरों के अलावा छोटे शहरों में भी इस तरह के घिनौने अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की साल 2020 की रिपोर्ट बताती है कि देश में बाल यौन शोषण के 47221 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में अधिकतर पीड़ित लड़कियां ही थीं। एनसीआरबी के मुताबिक यौन हिंसा और यौन शोषण की वारदातें सबसे अधिक 16 से लेकर 18 वर्ष की लड़कियों के साथ हुईं। इस क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार मामले पुलिस तक नहीं पहुंचते हैं या फिर परिवार ही बदनामी के डर से उसे दबा देता है। बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए नौ साल पहले पॉक्सो कानून बनाया गया था। सवाल यह है कि क्या कानून अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा है? 2016 से 2020 तक (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट किए गए बाल यौन शोषण के मामलों की संख्या 2016 में 36321 से बढकर 2020 में 47 हजार से अधिक हो गई। यह 31 प्रतिशत की वृद्धि है। विशेषज्ञों के अनुसार यह संख्या भी हिमखंड का सिरा मात्र है। एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में से सिर्फ 36 फीसदी ही पॉक्सो के तहत दर्ज होते हैं। बदलती तकनीक और इसके दुरुपयोग के साथ तालमेल रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों की विफलता की जांच करने वाले अधिकार समूह 'इक्कालिटी नाउ' का कहना है कि संभावित पीड़ितों को लक्षित करने के लिए शिकारी तेजी से सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं।

इक्कालिटी नाउ के मुताबिक अपराधी गुमनाम तरीके से काम करते हैं और वे बहुत सीमित विनियमन के तहत काम करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बच्चियों के माता-पिता के मन का सबसे बड़ा डर जरूर है। यह कटु सत्य है कि हमारे देश में कुछ लोग लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत उत्सुक नजर नहीं आते। कहीं मां-बाप अपनी बच्चियों को घर से ज्यादा दूर भेजना नहीं चाहते, क्योंकि वे उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं रहते। तो कहीं वे उनकी पढ़ाई पर खर्च को फिजूल मानते हैं। कहीं घर की सोच सिर्फ लड़कों को पढ़ने की आजादी देती है, तो कभी कहीं किसी लड़नी के साथ हुई शोषण-उत्पीड़न की घटनाएं बाकी लड़कियों को भी घर में कैद होने को मजबूर कर देती हैं। अकसर गांव के स्कूलों में लड़कियां शिकायत को भी आगे इसलिए नहीं आती क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। फिर उनके लिए घर के चूल्हा-चौके से बाहर निकलने का यही एक रास्ता भी होता है। उनकी आवाज भी कई बार इज्जत के नाम पर दबा दी जाती है। पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून हमारे यहां बहुत मजबूत है, बावजूद इसके किसी में इसका डर नहीं है क्योंकि लड़कियों की स्थिति हर किसी को पता है, जो कभी डर तो कभी लालच से इन घटनाओं को छिपाने को मजबूर हो जाती हैं। गांव के स्कूलों में तो गुड टच-बैड टच किसी तरह की जागरूकता भी नहीं है। जब तक कोई बड़ी घटना सामने नहीं आती, कोई हलचल तक नहीं होती। और ऐसा भी नहीं कि इसका सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है। यह पूरा सांठगांठ का एक खेल होता है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक कई लोगों का हाथ होता है और कई बार तो शासन-प्रशासन की संलिप्तता भी देखने को मिलती है। इस ओर सरकार और महिला आयोग का ध्यान बिल्कुल ही नहीं जाता, जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता। क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जब बेटी स्कूल में ही सुरक्षित नहीं है तो पढ़ाई कैसे करेगी? हम खुद को भले ही कितना आगे बढ़ता हुआ देखें, भले ही हमने चांद पर कदम रख लिया हो, चाहे क्यों न हमने पृथ्वी के साथ मंगल ग्रह में भी अपना परचम फहरा दिया हो, लेकिन जब तक देश की बेटी ही सुरक्षित न हो तो ऐसे देश के विकासशील होने का भला क्या फायदा।

गौरतलब है कि कई बार स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक लड़कियों ने अकेले और सामूहिक रूप से यौन शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की है।

हालांकि यह हिम्मत हर स्कूल और कॉलेज परिसर में देखने को नहीं मिलती। सच्चाई की तह तक जाएं तो कहीं न कहीं स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर यह प्रश्नचिह्न उठाया जा सकता है। इसलिए लड़कियों के ड्रॉपआउट को कम करने के लिए सबसे पहले सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम के साथ ही अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है, जिससे लड़कियों के हौसले बुलंद हो सकें, मां-बाप भी निश्चिंत हो सकें और लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर आजादी से जीवन जी सकें। कन्या पूजन के इस देश में स्कूल छात्राओं के यौन शोषण के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा भी कम ही है।

भारत ने जिस बांग्लादेश को आजाद कराया वही बन गया 'दुश्मन'

5 दिसंबर का दिन भारत और बांग्लादेश दोनों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। 1971 में इसी दिन भारत ने बांग्लादेश को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। यह पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका था। तब भारत की मदद से बांग्लादेश की सेना ने ढाका को स्वतंत्र कराया था। इसके लिए पाकिस्तानी सैनिकों को बेशर्त आत्मसमर्पण कराया गया था। भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं ने साल 1971 में एक बड़ा युद्ध लड़ा था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। यह युद्ध तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में लड़ा गया था, जहां शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बंगालियों ने पाकिस्तान से आजादी के लिए विद्रोह कर दिया था। भारत ने विद्रोहियों का समर्थन किया और इस तरह बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का उदय हुआ। भारत बांग्लादेश का सबसे करीबी साझेदार बन गया। शेख मुजीब ने भारत के साथ दोस्ती को विदेश नीति की आधारशिला घोषित किया, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में चीजें बदलने में देर नहीं लगतीं। यहां भी ऐसा ही हुआ और कुछ ही सालों में चीजें खराब हो गईं। संघर्ष के चलते बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बर्बाद थी। आर्थिक तंगी से परेशान लोगों के बीच जल्द ही यह धारणा फैलने लगी कि भारत इसके लिए जिम्मेदार है। आम बांग्लादेशी के मन में यह बात बैठ रही थी कि भारतीय व्यापारी देश की संपत्ति लूट रहे हैं। गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद ने भी इसमें भूमिका निभाई और कहा जाने लगा कि भारत बांग्लादेश को सूखा करने की कोशिश कर रहा है।

बांग्लादेश में भारत की बिगड़ती छवि को सुधारने के लिए शेख मुजीब का भी कोई ध्यान नहीं था। मुजीब ने भारत के प्रभाव को कम करने के लिए सावधानी से काम किया और भारत समर्थक नेताओं को सत्ता से बाहर रखा। 1971 के कुछ ही सालों के भीतर बांग्लादेश में भारत ने अपना प्रभाव खो दिया था। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने शेख मुजीब को समर्थन जारी रखा। भारत की मुख्य कोशिश हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को रोकना और पूर्वी हिस्से को स्थिर रखना था। भारत यह भी चाहता था कि पाकिस्तान यहां से बाहर रहे और ढाका की सरकार 1971 के पूर्व की तरह पूर्वोत्तर में विद्रोहियों को सहायता प्रदान न करे। मुजीब ने भारत की इन मांगों को पूरा किया। लेकिन इस बीच मुजीब के लिए अंदर हालात खराब हो रहे थे। 1974 में बांग्लादेश में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। मुजीब तानाशाह बनते जा रहे थे। उन्होंने एक पार्टी का शासन बनाया और आपातकाल लागू कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश के सुरक्षा बल जेआरबी को अपनी निजी सेना में बदल दिया। जेआरबी को उनके समर्थन ने सेना में कई लोगों को डरा दिया।

साल 1975 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख आरएन काव ने मुजीब को व्यक्तिगत रूप से बताया कि उनकी जान को खतरा है। मुजीब ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसी साल 15 अगस्त, 1975 को सेना के कुछ अफसरों ने उनके घर में घुसकर कोहराम मचाया। इसमें शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई। मुजीब की मौत के कुछ दिनों के भीतर ही कई भारत समर्थक नेताओं की हत्या हुई। भारत के लिए यह बड़ा झटका था।

खांडकर मुश्ताक अहमद ने सत्ता संभाली और जल्द ही भारत को समझ आ गया कि पाकिस्तान समर्थक सरकार सत्ता में आ गई है। पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब नई सरकार के बहुत करीब आ गए थे। 1975 में एक समय ऐसा आया जब भारत सैन्य हस्तक्षेप करने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद साल 1976 में जनरल जियाउर रहमान ने बांग्लादेश में सत्ता पर कब्जा कर लिया। जिया ने देश को इस्लामिक गणराज्य न घोषित करने पर सहमति जताई। लेकिन अभी भी नई दिल्ली और ढाका के बीच संदेह था।

इस बीच जनरल जिया ने भारत के पूर्वोत्तर में विद्रोही समूहों के लिए धन मुहैया कराना फिर से शुरू कर दिया। जल बंटवारे जैसी द्विपक्षीय समस्या को गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे वैश्विक मंचों से उठाया। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाए। इस तरह बांग्लादेश भारत के खिलाफ साफ नजर आने लगा था। विशेषज्ञ बांग्लादेश के दूर निकलने की वजह भारत की गलतियों को मानते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने केवल मुजीब पर दांव लगाकर गलती की। शेख मुजीब की तानाशाही नीतियों के बावजूद नई दिल्ली ने उन्हें पूरा समर्थन दिया, जिससे बांग्लादेश में भारत की छवि पर असर पड़ा। सिर्फ एक नेता चुनने और बाकी को दरकिनार करने की इस नीति की हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ी।

भारत और बांग्लादेश में अविश्वास का चक्र लंबे समय तक जारी रहा। शेख हसीना की सत्ता में वापसी ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में मधुरता देखी, क्योंकि उन्होंने भारत समर्थक नीतियां अपनाईं। हालांकि, उनका शासन निरंकुश रहा, जिस कारण भारत का समर्थन कई बांग्लादेशियों को पसंद नहीं आया। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अब भारत के पास अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अल्पकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय, लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्माण और बांग्लादेशी आबादी के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने में निवेश करना चाहिए।

कब रुकेंगी मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं?

यह घटना आपको भीतर तक झकझोर देगी... राजस्थान के बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र में एक महिला को डायन बताकर न केवल गर्म सलाखों से दागा गया, बल्कि बाल तक काट दिए गए। मुंह काला कर गांव में घुमाया गया और पेड़ से बांध दिया गया। मल-मूत्र तक खिला दिया गया। यह सब महिला की बीमारी ठीक करने का बहाना बनाकर किया गया। विडंबना यह है कि आज भी देश के अलग-अलग इलाकों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। भले भारत की साक्षरता दर 74 प्रतिशत से अधिक हो गई हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे जादू-टोना करने वालों के चंगुल में फंसते रहते हैं। एक समय ऐसा भी था, जब यूरोप द्वारा भारत को जादू-टोने का देश तक बता दिया जाता था, लेकिन पिछले सात दशक में हमने न केवल तरक्की की ऊंचाइयों को छुआ है, बल्कि इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) जैसे क्षेत्रों में दुनिया को राह दिखा रहे हैं। हमारे इंजीनियर अमेरिका की सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं। आज दुनिया में उपलब्ध हर आधुनिक वस्तु भारत में आसानी से मिल जाती है। कई देशों के लोग भारत में इलाज कराने आते हैं, क्योंकि हमारे यहां अच्छे डॉक्टर हैं और हमारी मेडिकल साइंस ने खूब तरक्की की है। फिर भी कुछ लोग भोपा या जादू-टोना करने वालों के फेर में आ रहे हैं। या तो उन्हें उचित इलाज नहीं मिल रहा होता या वो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं। जब कोई व्यक्ति निराशा होता है तो ऐसे फर्जी लोगों का निशाना बन जाता है, जैसा बूंदी जिले के हिंडोली की महिला के साथ हुआ। महिला को मात्र पेट में दर्द था और वो ठीक नहीं हो रहा था। कमाल की बात यह है कि भोपा महिला को प्रताड़ित करता रहा और किसी ने विरोध तक नहीं किया। हालांकि, अब महिला के परिजनों ने भोपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भोपा गैंग के साथ फरार हो गया है। भोपा या जादू-टोना करने वाले केवल पिछड़े या ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं हैं। इनकी जड़ें दिल्ली समेत अधिकांश शहरों में जमी हुई हैं। बड़े-बड़े शहरों के चौराहों पर अक्सर आपको ऐसे कार्ड बांटने वाले मिल जाएंगे, जो वशीकरण, मनचाहा प्यार, गृह क्लेश, जादू-टोना, पति-पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं। जब कोई व्यक्ति चारों ओर से निराश होता है तो इन जादू-टोटका करने वालों के फेर में आ जाता है। बस यही पर किसी भी व्यक्ति के धैर्य और सोच-समझ की परीक्षा होती है। हमें ये समझना चाहिए कि यदि कोई बीमार है या जीवन में परेशानी है तो उसका इलाज डॉक्टर या वैद्य के पास मिलेगा। कई बार हम डॉक्टर से इलाज कराते-कराते उस स्थिति में इलाज को छोड़ देते हैं, जब बीमारी ठीक होने वाली होती है। फिर जादू टोटका करने वालों के फेर में आ जाते हैं और दो-चार लोगों को राहत मिलती है तो वो इनका मुफ्त में प्रचार करने लग जाते हैं। ऐसे फर्जी लोग केवल अपने ठिकाने बनाकर नहीं बैठे हैं, बल्कि बाकायदा खुले मंच सजाकर भी बीमारियां ठीक करने का स्वांग रचते हैं। ऐसे सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। डायन प्रथा को लेकर कोई केंद्रीय कानून तो नहीं है, लेकिन राज्यों में अपने-अपने यहां कानून बना रखे हैं। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 और राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण नियम 2016 के तहत किसी महिला को डायन घोषित कर बदनाम या प्रताड़ित कर नुकसान पहुंचाने पर अपराधी को 1 से 5 साल तक कठोर कारावास या 50,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र, जादू-टोटका कर किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाता है तो उसे 1 से 3 साल तक का कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। वैसे तो शासन-प्रशासन डायन प्रथा को लेकर समय-समय पर जन-जागरूकता के कार्यक्रम चलता है, लेकिन सोशल मीडिया पर खुलेआम फर्जी दावे कर रहे तत्वों पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। सरकारी बसों में ऐसे स्टिकर लगे मिल जाते हैं, जो वशीकरण, बीमारियों का शर्तिया इलाज आदि का दावा करते हैं, जबकि उनके पास कोई भी मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं होती। कुछ लोग बाकायदा बड़े आयोजन का स्टेज सजाकर बीमारियों को ठीक करने का ड्रामा करते हैं।

एक हाथ में माला एक हाथ में भाला

संगठन में ही शक्ति है संगठन ही भारत की पहचान है पीयूष दास महाराज

उमेश कुशवाहा | सिटी चीफ

सतना, सतना सनातन चेतना मंच द्वारा गुरुनानक दरबार सिटी कोतवाली के पीछे मैदान में साधु संत की उपस्थिति में बृहद धरना प्रदर्शन और विशाल रैली के साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सनातन चेतना मंच के संयोजक पीयूष जी महाराज- हम सब सामर्थ्यवान है समय आने पर एकजुट खड़े होते हैं। संगठन में ही शक्ति है। संगठन ही भारत की पहचान है। आज बांग्लादेश में सनातन का गला रेता जा रहा है। साधू संतो को जेल भेजा जा रहा है। यह हिंदुत्व की आत्मा पर क्रूर हमला है। वहाँ हिंदुओ के घर जलाए जा रहे हैं विग्रह तोड़े जा रहे हैं। हम आज नहीं जागे तो फिर हमारे अस्तित्व को कोई नही बचा पाएगा। प्रणामी समाज की साध्वी निर्मला देवी ने कहा कि केवल एकता और सामूहिक प्रयास से ही इन कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। उनके अनुसार, यह समय हिंदू समाज के लिए जागरूकता और सक्रियता दिखाने का है।उनका संदेश मुख्य रूप से एकजुटता और संगठन की शक्ति पर आधारित है। उन्होंने यह आह्वान किया है कि यदि हिंदू समाज इन परिस्थितियों में नहीं जागेगा और संगठित होकर कदम नहीं उठाएगा, तो भविष्य में उनकी पहचान और अस्तित्व को बचाना कठिन हो सकता है।

सिंधी समाज के संत बाबा दयाल दास गुरुद्वारा के महंत बाबा पुरुषोत्तमदास जी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज संतों के हाथ में माला और भाला दोनों की आवश्यकता है। उन्होंने इसे मानवता और धर्म के लिए एक गंभीर चुनौती बताया। उनके अनुसार, वहां हो रही घटनाएं न केवल पीड़ा का कारण हैं, बल्कि यह हिंदू समाज के लिए एक चेतावनी भी हैं कि हमें जात-पात और आंतरिक भेदभाव को छोड़कर एकजुट होने की आवश्यकता है।महाराज जी ने अपने संदेश में एकता और भाईचारे का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, जाति-पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई-भाई। यह संदेश इस बात पर बल देता है कि जब तक हिंदू समाज आपसी विभाजन को समाप्त नहीं करेगा, तब तक वह बाहरी चुनौतियों का सामना प्रभावी रूप से नहीं कर पाएगा।उन्होंने यह भी कहा कि समाज की एकता ही उसकी शक्ति है और यही हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा का सबसे मजबूत साधन है। उनका संदेश सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने और एकता बनाए रखने की प्रेरणा देता है।

श्री गुरुद्वारा नानक दरबार के प्रमुख सेवादार बाबू लजपाल सिंह भाटिया ने कहा कि यदि हम संगठन और एकजुटता के महत्व को नहीं समझते, तो इन चुनौतियों से पार पाना मुश्किल होगा।

दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ समाजसेवी रमेश जैन ने अपने बयान में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन घटनाओं के लिए कहीं न कहीं हमारी अपनी कमजोरियां भी जिम्मेदार हैं, विशेष रूप से समाज में एकता की कमी।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हमें इन घटनाओं की जानकारी नहीं है, और यदि पता है तो अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। उनके अनुसार, ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए हिंदू समाज को एकजुट होना होगा।

मंच मे साध्वी निर्मला दीदी, सोहावल बड़ा अखाड़ा स्वामी धरणीधरा चार्य छोटा अखाड़ा स्वामी आशुतोष जी झूलेलाल मंदिर से संत समानामल जी मेहरशाह दरवार से पुरुषोत्तम दास जी, राम जानकी मंदिर से संत श्री गणेश महाराज, और सनातन चेतना मंच के संयोजक पीयूष दास महाराज डालीबाबा मंदिर की उपस्थित रहे।

इस दौरान शिवराम जी समदड़िया ,प्रांत संगठन मंत्री अमित दवे, उत्तम बनर्जी योगेश ताम्रकार मणिकांत माहेश्वरी श्रवण सैनी इंजी रमेश जैन सतीश शर्मा संजय सिंघई

नरेंद्र त्रिपाठी लक्ष्मी यादव विनोद यादव रविन्द्र सिंह विनोद तिवारी सतीश सुखेजा जितेन्द्र सिंह नीरज शुक्ला लखन लाल केसरवानी मनमोहन माहेश्वरी श्याम लाल गुप्ता श्यामू मनोहर वाधवानी दीपक शुक्ला हरिओम गुप्ता जितेंद्र जैन रविशंकर गौरी ममता पांडेय विमला पांडेय जान्हवी त्रिपाठी इंजी भास्कर भट्टाचार्य इंजी प्रकाश गौतम भास्कर चतुर्वेदी संजीव महेश्वरी रामावतार चमाडिया उमेश दुबे ज्ञानेंद्र मिश्रा लवकुश पांडे ऋषभ सिंह अशोक अग्रवाल सहित हजारों की संख्या में उपस्थित रहे।

महिला एवं बाल विकास विभाग का हम होंगे कामयाब अभियान

माडल स्कूल अनूपपुर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सुशिल सोनी | सिटी चीफ

मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा विशेष जागरूकता अभियान हम होगें कामयाब पखवाड़ा दिनाँक 25.11.2024 से 10.12.2024 तक चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य मे महिला थाना अनूपपुर द्वारा आज दिनाँक 04.12.2024 को माडल स्कूल अनूपपुर मे जाकर विशेष जागरूकता अभियान हम होगें कामयाब के अन्तर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संसाधन केन्द्रो/लोक अधिकार केन्द्र और वन स्टॉप सेंटर तथा उर्जा महिला डेस्क के बीच समन्वय कर हिंसा उन्मुलन हेतु कार्ययोजना विषय पर चर्चा कर छात्र - छात्राओ एवं विद्यालय स्टाफ को विस्तृत जानकारी दी जाकर जागरूक किया गया । जागरूकता अभियान मे माडल स्कूल अनूपपुर में करीब 200 छात्र - छात्राए एवं विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे है । महिला थाना अनूपपुर स्टाफ उपनिरी. वीरेन्द्र तिवारी, आर. कपिल देव चक्रवर्ती, म.आर. प्रवीन गौतम द्वारा जागरूकता अभियान की विस्तृत जानकारी छात्र- छात्राओ को दी गई ।

ऑपरेशन मुस्कान के तहत कोतवाली पुलिस ने 7 दिन में 12 गुमशुदा महिला एवं पुरुष को तलाश कर परिजनों को सौंपा, लौटाई खुशियां

यशपाल सिंह जाट | सिटी चीफ

अनूपपुर, पुलिस अधीक्षक श्री मोती उर रहमान के निर्देशन में कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत थाने में दर्ज गुमशुदगी के विभिन्न प्रकरणों में लापता महिला और पुरुषों की तलाश कर उन्हें परिजनों को सुपुर्द किया गया। दिनांक 28.11.2024 से 04.12.2024 के बीच 7 दिन के इस अभियान में थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद जैन के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक आशीष सिंह, सहायक उपनिरीक्षक संतोष पांडेय, प्रधान आरक्षक राजकुमार साहू, रीतेश साहू और आरक्षक अमित यादव की टीम ने 12 गुमशुदा व्यक्तियों को खोजकर उनके परिजनों को सौंपा।

इनकी तलाश में मिली सफलता- पुलिस टीम ने रजनी बाई (32 वर्ष) निवासी ग्राम दुधमनिया , सुनैना कोल (19 वर्ष) निवासी ग्राम पिपरिया , गडुल सिंह (24 वर्ष) निवासी ग्राम बड़हर, दुर्गावती सिंह (28 वर्ष) निवासी ग्राम सकरा, गिरजा सिंह उर्फ गुड्डू (28 वर्ष) निवासी ग्राम खांडा, राजेश साहू (44 वर्ष) निवासी पुरानी बस्ती अनूपपुर , कंचन कोल (23 वर्ष) निवासी ग्राम कांसा , संतोषी कोल (21 वर्ष) निवासी ग्राम लखनपुर , लवकेश केवट (24 वर्ष) निवासी ग्राम कोलमी , आर्यन उर्फ जयेश सैनी (22 वर्ष) निवासी पटोराटोला अनूपपुर , सुमित्रा कोल (30 वर्ष) निवासी ग्राम परसवार और रश्मि यादव (19 वर्ष) ग्राम सीतापुर को विभिन्न स्थानों से बरामद कर उनके परिजनों को सुरक्षित सौंपा।

परिजनों की खुशी- अपने लापता प्रियजनों के घर लौटने पर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक अनूपपुर एवं कोतवाली पुलिस का आभार व्यक्त किया और उनके इस प्रयास की सराहना की।

पुलिस का अभियान जारी रहेगा-पुलिस अधीक्षक श्री मोती उर रहमान ने बताया कि गुमशुदा महिला एवं पुरुषों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान अभियान निरंतर जारी रहेगा। पुलिस का यह प्रयास परिवारों को राहत पहुंचाने और समाज में विश्वास कायम करने का कार्य करेगा।

झिरिया कोल माइन्स में बड़ा हादसा दो कर्मचारियों की मौत

सुरक्षा नियम का पालन न करने के कारण हुआ बड़ा हादसा, जिम्मेदार मौन

यशपाल सिंह जाट | सिटी चीफ

अनुपपुर, अनुपपुर जिले के अंतिम छोर में स्थित काले हीरे की खदान ने फिर दो लोगों की ली जान जिम्मेदार क्यों नहीं लेना चाहते इन हादसों की जिम्मेदारी । ये है पूरा मामला। अनुपपुर जिले अंतर्गत आने वाली झिरिया कोल माइन्स में आज लगभग 1 बज 30मिनट पर कोयले के बड़े पत्थर के नीचे दब कर दो एस ई सी एल के कर्मचारियों की मौत हो गई । जानकारी अनुसार इस खदान में खदान वापसी की ओर संचालित है एस डी एल मशीन के लिए जगह बनाने या लोडिंग प्वाइंट की जगह बनाने दागानी की गई इस दागानी की वजह से पत्थर का बड़ा हिस्सा ऊपर से गिर गया जिसके नीचे कर्मचारी दब गए दागनी में 51 टोपी की दागनी की गई सुरक्षा में चूक यही हुई दागनी के बाद कम से कम 30मिनट का इंतजार करने के बाद खदान की ऊपरी सतह को जांचते हुए ही कर्मचारियों को जाने की परमिशन माइन मैनेजर को देनी चाहिए ये सारी जिम्मेदारी माइन मैनेजर की होती है ।। एसईसीएल उपक्रम के हसदेव क्षेत्र के राजनगर उपक्षेत्र के झिरिया अंडरग्राउंड खदान में कोयले में ब्लास्टिंग करने के बाद ड्रेसिंग के दौरान पत्थर गिरने से दो श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें प्रबंधन के द्वारा केंद्रीय चिकित्सालय मनेन्द्रगढ़ ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। खान दुर्घटना में श्रमिक लखन लाल पिता चरकू एवं वॉल्टर तिर्की पिता लजरस तिर्की की मृत्यु हो गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनलाल एवं वॉल्टर नामक सपोर्ट पर्सन झिरिया खदान के अंदर कोयले में ब्लास्टिंग के उपरांत ड्रेसिंग कर रहे थे तभी ड्रेसिंग के दौरान एक श्रमिक के ऊपर छोटा पत्थर का टुकड़ा गिरा। उस श्रमिक को सहयोग करने के लिए दूसरा श्रमिक उसके नजदीक पहुंचा तब एक बड़ा कोयले का टुकड़ा इन श्रमिकों के ऊपर गिरा। सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि ब्लास्टिंग के करीब एक से डेढ़ घंटे बाद श्रमिक कोयल की ब्लास्टिंग की ड्रेसिंग कर रहे थे उसी दरमियान यह घटना घटी

कटनी में सनातन चेतना मंच ने किया प्रदर्शन

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा

सुनील यादव | सिटी चीफ बंगला देश में रह रहे अल्पसंख्यक हिन्दू बौद्ध ईसाई समुदाय के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज कटनी में सनातन चेतना मंच के सैकड़ों लोगों ने एक विशाल रैली निकालकर जिला कलेक्टर का घेराव कर ज़ोरदार प्रदर्शन करते हुए देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सनातन चेतना मंच के डॉक्टर अमित साहू ने बताया कि बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट के बाद वहां का माहौल बदल गया है वहां पर रह रहे अल्संख्यक हिंदुओं के मंदिर बौद्ध ईसाई धर्म के मंदिर गिरजाघर तोड़े जा रहे है,लोगों के घरों पर लूटपाट मची है दुकानों पर आग लगा कर जला दी गई है वही साथ ही 252 हिन्दू पुलिस अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है वही हिन्दू लड़की को जबरन धर्मांतरण कर आतंकी संगठन में शामिल किया जा रहा है जिसको लेकर आज भारत की महामहिम के नाम ज्ञापन दिया है, वही डिप्टी कलेक्टर ने सनातन चेतना मंच के ज्ञापन को सुना और महामहिम के नाम ज्ञापन को लिया।

बस स्टैंड बना अवैध शराब बिक्री का अड्डा

खाने के होटल की आड़ में जम कर हो रही कच्ची पक्की शराब की बिक्री

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ अनुपपुर, अनुपपुर जिले के जैतहरी नगर परिषद के बस स्टैंड में अवैध शराब बिक्री जोरो पर है जिसमें कच्ची पक्की दोनों प्रकार की अवैध शराब की बिक्री हो रही है , यहां अंडे एव बिरयानी दुकानों की आड़ में ये शराब का अवैध धंधा जोरो पर है , लल्लू गुप्ता कोमल राठौर एव मोहन द्वारा यहां ये अवैध शराब बिक्री का कार्य खुलेआम किया जा रहा है । ये जैतहरी का मुख्य बस स्टैंड होने के कारण यहां महिला यात्रियों का भी नियमित आना जाना लगा रहता है पर यहां खुलेआम यू शराब बिक्री एवं शराबियों का नियमित जमावड़ा लगा रहता है जिससे इन महिला यात्रियों को बस स्टैंड में बस की प्रतीक्षा करने के दौरान असहज महसूस होता है एवं हमेशा किसी अनहोनी का डर बना हुआ रहता है । यह बच्चों का भी नियमित आना जाना लगा हुआ रहता है क्योंकि जैतहरी के पास के गांव से आने वाले स्कूलों के छात्र छात्राएं बस से आना जाना करते है ,उनके ऊपर भी इस खुलेआम अवैध शराब बिक्री होने पर गलत प्रभाव पड़ता है । बस स्टैंड एक सामाजिक स्थल है और यहां इस प्रकार से शराब की अवैध बिक्री समाज के लिए काफी नुकसानदायक है , पुलिस के उच्च अधिकारियों से अनुरोध है कि सामाजिक स्थल की मर्यादो को बचाया जाए एव इन अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही कर इसपर पूरी तरह रोक लगाई जाए।

बांग्लादेश में हिंदूओं पर हो रही हिंसा के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन

हिंदू सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की मांग

भगवान दास बेरागी | सिटी चीफ

शाजापुर, बांग्लादेश में हिंदूओं के साथ कट्टरपंथियों के द्वारा की जा रही हिंसा के विरोध में शाजापुर जिला मुख्यालय पर जिलेभर के हिंदू समाजजनों ने विशाल धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बुधवार दोपहर 1 बजे स्टेडियम ग्राउंड पर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया जिसके मुख्य अतिथि संत रघुनाथदासजी महाराज थे। वहीं अध्यक्षता श्री 1008 उदयभान महाराज ने की। मुख्य वक्ता के रूप में भगवत मर्मज्ञ श्याम मनावत, मनोज परमार, अनुराधा नागर मौजूद रहीं। अतिथियों ने धरना आंदोलन को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों के द्वारा हिंदू समाज के लोगों की निर्मम हत्या की जा रही है, लेकिन इस हिंसा को रोकने के लिए किसी देश ने आवाज नही उठाई है, लेकिन भारत का हिंदू बांग्लादेश के हिंदूओं के साथ खड़ा हुआ है। उन्होने कहा कि भारत देश में भी असुरी शक्तियां बढ़ रही हैं, ऐसे में यदि हिंदू बंटेगा, तो कटेगा। आज जात, पात, ऊंच, नीच से उठकर एक होने की आवश्यकता है।

दरगाह नही दुर्गा पूजने की जरूरत धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अनुराधा नागर ने कहा कि आज दरगाह पूजने की नही दुर्गा पूजने की जरूरत है। उन्होने कहा कि नारी को सशक्त करने के लिए उसके हाथों में हथियार होना बेहद आवश्यक है, लेकिन देखने में आ रहा है कि समाज के कई लडके और लड़कियां रील में उलझी हुई हैं। उन्होने मंच से आह्वान किया कि रील में नही रियल में हिरो बनो और स्वयं की सुरक्षा को लेकर तैयार रहो। यदि आज नही संभले तो बांग्लादेश जैसे हालत भारत में भी हो सकते हैं। इसीके साथ अन्य वक्ताओं ने भी हिंदू समाज को एकजुट होकर रहने का आह्वान किया। इसके बाद कलेक्टर ऋजु बाफना को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि चिन्मय प्रभु की बिना शर्त रिहाई कराई जाए, बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाया जाए कि वह हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और धार्मिक ग्रंथों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिन हिंदूओं को उनकी जमीन, घरों से बेदखल किया गया है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे।

सिंगल क्लिक से जिले के 114 हितग्राहियों को 2.66 करोड़ रुपये की राशि का वितरण

भगवान दास बेरागी | सिटी चीफ

शाजापुर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग में बुधवार को सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत 10, 236 श्रमिक परिवारों को 225 करोड़ की अनुग्रह राशि का अंतरण किया गया। इस योजना में शाजापुर जिले के 114 हितग्राहियों को 2.66 करोड़ रुपये की राशि का वितरण भी शामिल है। शाजापुर जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अन्तर्गत मृत्यु की दशा में अनुग्रह भुगतान योजना सामान्य मृत्यु एवं दुर्घटना मृत्यु के स्वीकृति पश्चात् ईपीओ हस्ताक्षर किए गए। वहीं दुर्घटना मृत्यु के 19 प्रकरणों में एवं सामान्य मृत्यु के 95 प्रकरणों में राशि 2 करोड़ 66 लाख रुपये वन क्लिक के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित की गई। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान शाजापुर में कलेक्टर ऋजु बाफना, जिला पंचायत सीइओ संतोष टैगोर, प्रभारी श्रम पदाधिकारी आरएस चौहान सहित संबल हितग्राही मौजूद थे। कलेक्टर बाफना ने संबल हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण भी किया।

भारतीय सेना से सेवा निवृत्त होने पर तिरंगा यात्रा निकालकर सैनिक को किया सम्मानित

भगवान दास बेरागी । सिटी चीफ

शाजापुर, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए सैनिक का बेरछा पहुंचने पर स्वागत-सम्मान किया गया। समीपस्थ ग्राम उदली निवासी हवलदार दिनेशसिंह गुर्जर पिता बंशीलाल गुर्जर भारतीय सेना में 20 वर्ष की गौरवमयी सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर बेरछा पहुंचे, जिनका तिरंगा यात्रा निकालकर देश भक्ति के तराने डीजे की धुन पर थिरकते हुए पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही पूर्व में सेवानिवृत हुए सैनिक लच्छीराम गुर्जर निवासी सेतखेड़ी का भी स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक अरुण भीमावद, महेंद्र सोनी, वरिष्ठ समाजसेवी हाजी मुन्ना पठान, एडवोकेट सईद पठान, जिला पंचायत सदस्य जगदीश कराड़ा, एडवोकेट सावेद पठान, डॉक्टर शाहरुख पठान, परमानंद गुर्जर, अकबर अली खान, सौदानसिंह, समीउल्ला मामा, बालचंद्र अंसल, मुकेश वर्मा, मो. हुसैन मंसूरी, रसीद खान, सुनील परमार सहित नगरवासी मौजूद थे।

उपार्जन केन्द्र सेवा सहकारी समिति केवलारी अम्बिका सोया प्लांट पथरिया के स्थान में संशोधित करते हुए नवीन उपार्जन केन्द्र स्थल मंगलमूर्ति वेयर हाउस सूखा किया गया

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ

दमोह, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को आज अपने भ्रमण के दौरान जॉच समय उपार्जन केन्द्र के खरीदी स्थल अम्बिका सोया प्लांट पर कृषकों द्वारा बताया गया कि सुपरवाईजर निरंजन के द्वारा सभी कृषकों के साथ-साथ समिति कर्मचारियो को कई परेशानियों का समाना करना पड़ रहा है, जैसे कि किसानों की एंट्री के लिए समय पर गेट न खोलना, कि?सानों की समय से पहले खरीदी बंद करा देना, सभी से अभ्रदता से बातचीत करना ऐसी कई समस्याएं सभी द्वारा बताई गई एवं स्वयं मौका स्थल पर जाकर निरीक्षण टीम द्वारा देखी गई। कलेक्टर ने गोदाम सुपरवाईजर द्वारा किये गये कृत्य से सोयाबीन खरीदी कार्य लगातार प्रभावित होने पर अम्बिका सोया प्लांट में संचालित सोयाबीन उपार्जन केन्द्र का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए अम्बिका सोया प्लांट गोदाम को उपार्जन कार्य से पृथक कर दिया है। उन्होंने आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि भण्डारित स्कन्ध का रख रखाव गोदाम संचालक सुनिश्चित करेगे। सेवा सहकारी समिति केवलारी द्वारा संचालित सोयाबीन उपार्जन केन्द्र का उपार्जन स्थल जिला उपार्जन समिति द्वारा लिये गये निर्णय उपरांत स्थानांतरित कर दिया है जिसके अनुसार उपार्जन केन्द्र सेवा सहकारी समिति केवलारी अम्बिका सोया प्लांट पथरिया के स्थान में संशोधित करते हुए नवीन उपार्जन केन्द्र स्थल मंगलमूर्ति वेयर हाउस सूखा किया गया है।

देवबंद के होनहार टेनिस खिलाड़ी मोहम्मद अहमद का आईएसपीएल-2 के लिए हुआ चयन

गौरव सिंघल। सिटी चीफ

सहारनपुर । देवबंद, खड़ंजा अहमदपुर गांव के होनहार टेनिस खिलाड़ी मोहम्मद अहमद का चयन आईएसपीएल (इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग) के लिए हुआ है। 25 जनवरी से मुंबई में होने वाले खेलों के लिए 11 दिसंबर को खिलाड़ियों की बोली लगेगी और इस सूची में मोहम्मद अहमद का नाम भी शामिल है। खड़ंजा अहमदपुर निवासी किसान मोहम्मद शमशाद के पुत्र मोहम्मद अहमद ने बताया कि आईएसपीएल-2 के लिए देश भर से 40 लाख खिलाडियों ने ट्रायल दिया था। पहला ट्रायल मेरठ में और दूसरा व तीसरा ट्रायल इंदौर में हुआ था। इनमें से लगभग 220 खिलाडियों का चयन प्रीमियर लीग के लिए हुआ है। उनका नाम भी चयनित खिलाड़ियों की सूची में शामिल है। बताया कि जनपद सहारनपुर से वह अकेले खिलाड़ी है, जिनका चयन प्रीमियर लीग के लिए हुआ है। इसके लिए उन्हें ब्लू टिकट मिल गया है। मुंबई में होने वाले खेलों के लिए अब विभिन्न टीमें बोली लगाएंगी। बताया कि प्रीमियर लीग के लिए कुल छह टीमों की तरफ से बोली लगाई जाएगी। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी की लहर है। ग्रामीणों समेत गणमान्यों ने उन्हें बधाई दी है।

सहारनपुर जनपद में 08 दिसम्बर से चलेगा प्लस पोलियो अभियान, 09 से 13 दिसम्बर तक घर-घर जाकर पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप

अभियान की सफलता के लिए तैयार करें बेहतर माइक्रो प्लान -जिलाधिकारी मनीष बंसल

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में 8 दिसंबर से शुरू होने वाले प्लस पोलियो अभियान के सफल क्रियान्वयन के संबंध में तैयारियों को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गयी।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सभी अधिकारियों को 8 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सक्रिय सहभागिता निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि 09 दिसम्बर से 13 दिसम्बर तक घर-घर जाकर शत-प्रतिशत बच्चों का आच्छादन सुनिश्चित करें। जिले के चिह्नित हाइरिस्क एरिया, ईंट भट्टों, निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शनसाइट के पोलियो टीकाकरण पर विशेष ध्यान दें और पोलियो बूथ पर अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के विशेष प्रयास करें। डीएम मनीष बंसल ने कहा कि कोई भी बच्चा वैक्सीनेशन से वंचित नहीं रहे इसलिए शत-प्रतिशत टीकाकरण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग एवं पंचायती राज विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करे कि सभी बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाए। इसके लिए एमओआईसी एक बेहतर माइक्रोप्लान तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि पल्स पोलियो अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए ग्राम प्रधानों का सहयोग लिया जाए।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 प्रवीण कुमार, पीडी डीआरडीए प्रणय कृष्ण, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी श्रीमती पूजा शर्मा सहित समस्त एमओआईसी एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आयुष विभाग द्वारा चलाया जा रहा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ

दमोह, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली में आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवम्बर से 25 दिसम्बर 2024 तक चलने वाले आयुष विभाग द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का शुभारंभ कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नेतृत्व में एवं जिला आयुष अधिकारी डॉ. राजकुमार पटेल के मार्गदर्शन में प्रथम चरण के अंतर्गत आयुष विभाग, दमोह की सभी संस्थाओं पर आयुष चिकित्सकों के द्वारा जिले के लोगों की प्रकृति का परीक्षण एप के माध्यम से किया जा रहा हैं।

जिला आयुष अधिकारी डॉ. राजकुमार पटेल ने बताया कि प्रकृति परीक्षण करने के लिए लोगों को अपने मोबाईल पर एप स्टोर/प्ले स्टोर के माध्यम से Prakruti Parikshan App सर्च कर डाउन लोड करना पड़ेगा। जिसमें सिटीजन के रूप में लॉगन करने के लिए अपना मोबाईल नम्बर दर्ज कर ओ.टी.पी. के माध्यम से लॉगिन कर व्यकिगत जानकारी भरने पर क्यूआर कोड जनरेट होगा। जिसे विभाग के आयुष चिकित्सकों को आगे के प्रकृति परीक्षण की प्रक्रिया के लिए क्यूआर दिखाना अनिवार्य होगा। ग्राम सदगुवां आयोजित दिवस के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह अर्पित वर्मा को बताया कि पहले चरण में 18 वर्ष के ऊपर सभी लोगों का प्रकृति परीक्षण किया जाना हैं। जिसमें संबंधितों शरीर की आकृति, नेत्र, नख, केश, चयापचय, स्वेद धी, धृति, स्मृति, मानसिक व्यवहार आदि 22 प्रश्नों/उप प्रश्नों के माध्यम से लोगों के प्रकृति का पता लगाया जायगा। अंत में मोबाईल पर प्रकृति से संबंधित प्रमाण पत्र जारी होगा एवं प्रकृति के आधार पर लोगों को आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या एवं स्वस्थ्य जीवन शैली से संबंधित मार्गदर्शन तथा दिशा-निर्देश समय-समय पर आयुष विभाग द्वारा संबंधित के मोवाईल पर नोटीफिकेशन के माध्यम से दिये जायेगें।

उन्होंने जिले के समस्त नागरिकों से आग्रह करते हुये कहा है कि आयुष विभाग दमोह द्वारा चलाए जा रहे देश का प्रकृति परीक्षण अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी प्रकृति का परीक्षण करायें।

ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति उप्र ने सांसद चन्द्रशेखर को ज्ञापन देकर उप्रः के ग्राम प्रहरी चौकीदारो की वेतन वृद्धि कराने और राज्य कर्मचारी का दर्जा एवं अन्य सुविधा प्रदान कराने के संबंध में आवाज उठाने की मांग की गई

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर, ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद एड0 चन्द्रशेखर आजाद को ज्ञापन देकर उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी चौकीदारो की वेतन वृद्धि कराने और राज्य कर्मचारी का दर्जा एवं अन्य सुविधा प्रदान कराने के संबंध में आवाज उठाने की मांग की। समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने छुटमलपुर स्थित सांसद आवास पर पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद को जन्मदिन की बधाई दी और पिछले संसद सत्र में चौकीदारों की आवाज उठाने पर उनका आभार जताते हुए सम्मान किया। संसद को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि समस्त ग्राम प्रहरी चौकीदार के प्राधिकार वेतन वृद्धि से सम्बन्धित प्रदेश सभी जनपदो से लेकर, राजधानी, लखनऊ तक सप्रेम भेट वार्ता, ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति उ0प्र0 एवं ग्राम प्रहरी अधिकार मौर्चा के माध्यम से कई वर्षों से चौकीदार/ग्राम प्रहरी की मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाया गया, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले चौकीदार संगठन के प्रतिनिधियो को भाजपा कार्यालय लखनऊ में बुलाकर यह वादा किया गया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरियो/चौकीदारों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जयेगा। यदि सरकार नहीं बनती है तो केन्द्र सरकार के द्वारा 10500 मानदेय दिलाया जायेगा लेकिन दो बार प्रदेश में सरकार बनने के बावजूद भी मांगो को पूरा नहीं किया गया। 24 घंटे 30 दिन ग्राम प्रहरी गांव की निगरानी रखवाली करते हुए आपराधिक गतिविधियों की सूचना थानों पर देते हुए इसके एवज में उनको वेतन के स्थान पर 2500/ रूपये अल्प वेतन के रूप में दिया जा रहा है। जो कि इस महंगाई में बहुत की कम है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ग्राम प्रहरियो/चौकीदारो की मांग को पूरा किया जाये। प्रदेश के ग्राम प्रहरी/चौकीदारों को नियमित कर वेतन वृद्धि करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाये, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार ही ग्राम प्रहरियो/चौकीदारो को अधिकार दिया जाये, ग्राम प्रहरियो/चौकीदारों का निशुल्क इलाज ओर किसी घटना या दुर्घटना की स्थिति में 10 लाख रूपये तक का बीमा कराया जाए।

सांसद चंद्रशेखर आजाद ने चौकीदारों की आवाज उठाने और उनकी मांगों को पूरा करने के संबंध में काम करने का उन्हें आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष अनार चंद गौतम, मुहम्मद मंसूर अली जिलाध्यक्ष, प्रवक्ता विश्वास कुमार, समीर चंद, घनश्याम, श्याम कुमार, जहांगरी, सोनू, अनीस, धर्मपाल, भरत सिंह, रहीश व तेजपाल आदि मौजूद रहे।

सफाई कर्मचारियों ने किया डीएम के आदेशों का विरोध, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

बायोमैट्रिक उपस्थिति से मुक्त रखने की मांग की

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

देवबंद । सहारनपुर, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति के दिए गए आदेशों का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। जिसमें संघ ने बायोमेट्रिक उपस्थिति को असंभव बताते हुए इससे मुक्त रखे जाने की मांग की है। ब्लॉक कार्यालय परिसर में आयोजित हुई बैठक के बाद सफाई कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि शासन स्तर से ग्रामीण सफाईकर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक लगाई जाने का आदेश जारी नहीं हुआ है लेकिन इसके बावजूद डीएम सहारनपुर ने मनमाने तरीके से बायोमैट्रिक उपस्थिति का आदेश जारी किया है। जो शासनादेश के विरुद्ध है। कहा कि ग्रामीण सफाईकर्मियों की ड्यूटी समय-समय पर कांवड़ यात्रा, वीआईपी प्रोग्राम तथा निर्वाचन कार्यालय व अन्य सार्वजनिक प्रोग्रामों में लगाई जाती है। इतना ही नहीं सफाई कर्मी ड्यूटी करने के लिए दूर दराज इलाकों में भी जाते हैं, गांव में परिवहन साधनों की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बायोमैट्रिक उपस्थिति लगभग असंभव है। पत्र में कहा गया है कि गांव में
स्कूल टीचर भी हैं, ऐनम सेंटर भी हैं, सीएचसी भी है और इन सबके कर्मी भी शिक्षित हैं। लेकिन उनकी भी बायोमैट्रिक उपस्थिति नहीं होती है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को ऑनलाइन उपस्थिति से मुक्त रखा जाए।

राज्यमंत्री की संकल्प पदयात्रा दूसरे दिन उचेहरा से हुई शुरू

प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना कर पदयात्रा का हुआ समापन

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ

सतना, प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी की दो दिवसीय संकल्प यात्रा बुधवार को उचेहरा स्थित बंधन पैलेस शुरू हुई। संकल्प पद यात्रा के दौरान राज्यमंत्री श्रीमती बागरी ने कहा कि सेवा और समर्पण से जनकल्याण के कार्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यह पदयात्रा हमारी आस्था और जनता के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस मौके पर मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल, जिला अध्यक्ष कमलेश सुहाने, सांसद प्रतिनिधि संतोष सोनी सहित बडी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, ग्रामीणजन श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी की दो दिवसीय संकल्प पदयात्रा उचेहरा से मिड-वे एमपीटी, रामजी ढाबा टोल प्लाजा, रमपुरवा मोड, जीतनगर पेट्रोल पम्प, ओइला मंदिर, वल्लभ नगर, अम्बेडकर नगर, घंटाघर, अग्रसेन चौक, नगर पालिका चौक, बडा अखाडा, बंधा बैरियल होते हुए मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन, पूजा-अर्चना की। राज्यमंत्री श्रीमती बागरी ने मां शारदा देवी से प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना कर संकल्प पदयात्रा का समापन किया। संकल्प पदयात्रा के दौरान राज्यमंत्री श्रीमती बागरी का जगह-जगह पुष्पवर्षा कर दीप-कलश के साथ आत्मीयतापूर्ण भव्य स्वागत और आगवानी पुरूष एवं महिलाओं, ग्रामीण आमजनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई।

किसान देश की रीढ़ हैं....सरकार अपना वादा निभायें-अनुभा मुंजारे

जाम में किसानों के धरना प्रदर्शन विधायक अनुभा मुंजारे ने समर्थन दिया

लकेश पंचेश्वर | सिटी चीफ

लालबर्रा, बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने कहा कि किसान हमारे देश की रीढ़ हैं और रीढ़ को जिस तरह से प्रदेश व देश की बीजेपी सरकार प्रताड़ित व परेशान कर रही वह बहुत चिंतनीय हैं।किसानों से किये गये वादा को प्रदेश सरकार नहीं निभा रही हैं।किसानों से 31 सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीदी करने का वादा किया गया था जिसे सरकार निभायें।बता देवें कि बालाघाट विधानसभा के लालबर्रा क्षेत्र के जाम,बहेगांव,सिहोरा,कंजई सहित अन्य स्थानों पर धान की दर 31 सौ रूपये प्रति क्विंटल देने की मांग को लेकर किसानों द्वारा धान खरीदी स्थान पर ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा हैं। इस प्रदर्शन स्थल पर विधायक अनुभा मुंजारे पहुंची और उन्होने किसानों के साथ धरना दिया। किसानों की मांग का समर्थन किया और मांग को जायज बताते हुये प्रदेश सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी ना करते हुये किसानों की मांग को शीघ्र पूरी करने का आहवान किया हैं।विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि आज के दौर में किसान अपने हक व अधिकार के लिये सचेत है और अब वे मैदान में उतर गये हैं।किसानों का यह आंदोलन सही भी हैं क्योंकि जिन किसानों के भरोसे प्रदेश में बीजेपी सरकार काबिज हुई वह उन किसानों को भुलाने का कार्य कर रही हैं।श्रीमती मुंजारे ने कहा कि प्रदेश की सरकार जिन मुददों पर काबिज हुई थी उसमें दो प्रमुख तौर पर मुददे थे।जिसमें प्रथम मुददा लाड़ली बहनाओं को 3 हजार रूपये मासिक देने का और किसानों की धान की उपज को 3100 रूपये प्रति किवंटल, गेहूं 27 सौ रूपये व सोयाबीन 6 हजार रूपये प्रति क्विंटल तथा उज्जवला योजना की बहनों को 450 रूपये में गैस उपलब्ध कराना शामिल थे।लेकिन साल बीत गये पर प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इस वादा को पूरा नहीं किया हैं। विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने अपना 1 भी वादा को पूरा नहीं किया हैं। लाड़ली बहनों को महज साढ़े 12 सौ रूपये दे रही हैं। किसानों की उपज को 23 सौ रूपये में खरीदी की जा रही हैं। 2 दिसंबर से धान की खरीदी प्रारंभ हो गई हैं। धान की दर को लेकर किसानों से किसी तरह का विचार-विमर्श नहीं किया गया और ना ही किसानों को भरोसा में लिया गया और सीधे खरीदी की तारीख नियत कर खरीदना प्रारंभ कर दिया गया हैं।किसान अपनी उपज का सही दाम मांग रहे हैं और सरकार को उनका वादा याद दिलाते हुये 31 सौ रूपये की दर दिये जाने की मांग कर रहे हैं। यह मांग बहुत ही जायज हैं और सरकार को इस मांग को हर हालत में पूरी करना होगा। विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि वह किसानों की मांग का समर्थन कर रही हैं और इसी के चलते धरना प्रदर्शन में पहुंची हैं। किसानों के हर लड़ाई में हमारा साथ हैं। किसान जिस तरह से भी लड़ाई जारी रखेगें हमारा उनको हमेशा समर्थन रहेगा। यही नहीं आगामी 16 दिसंबर से प्रदेश का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने जा रहा हैं। इस सत्र में विधानसभा का घेराव व किसानों की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जायेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। जिन्होने सरकार से धान की खरीदी नहीं करने को लेकर नाराजगी जतायी और नारेबाजी की।

रामा मेडिकल स्टोर के अतिक्रमण पर नगर निगम चुप्पी सवालों में

दो बार अतिक्रमण हटाने के बाद भी तानाशाही पर उतारू रामा मेडिकल स्टोर का संचालक

उमेश कुशवाहा | सिटी चीफ

सतना, यूं तो शहर के प्रत्येक वार्ड में अतिक्रमण देखने को मिलेगा। लेकिन सीताराम पट्रोल पंप के पास वर्तमान समय में शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी रामा मेडिकल स्टोर संचालक का अतिक्रमण सुर्खियों में है। क्यों कि रामा मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा नगर निगम को सीधा चैलेंज किया जा रहा है। जानकारों की मानें तो विगत कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा रामा मेडिकल स्टोर द्वारा बनाई जा रही बिल्डिंग शासकीय आराजी में पाया गया था। जिसके बाद नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था। लेकिन इसके बाद भी रामा मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा फिर से उसी जगह पर अतिक्रमण कर लिया गया है। तो वहीं नगर निगम अतिक्रमण इस मामले को लेकर चुप्पी साधी गई है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में बिल्डिंग का निर्माण कार्य विगत कुछ दिनों से चल रहा था। अब देखना यह है कि इस मामले में अतिक्रमण विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है।

इनका कहना है..

उक्त अतिक्रमण दो बार हटाया जा चुका है। इसके बाद भी अगर अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है तो टीम भेजकर कार्यवाही करवाता हूं।

अंशुमान सिंह
अतिक्रमण प्रभारी
नगर पालिक निगम, सतना

कंजई मोक्ष धाम स्थित नाला हो रहा खोखला...?

राजस्व नाले से हो रहा रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन..

लकेश पंचेश्वर | सिटी चीफ लालबर्रा, लालबर्रा के कंजई गांव के मोक्ष धाम स्थित राजस्व नाले से प्रतिदिन सुबह चार पांच बजे के समय और रात के समय रेत का अवैध उत्खनन कर ट्रैक्टर से परिवहन हो रहा है बताया जा रहा है की रेत चोरी का काम गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है जिससे नाले में बड़े-बड़े गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं अवैध उत्खनन से शासन को रोजाना नुकसान उठाना पड़ रहा है पटवारी हल्का क्षेत्र मे हो रहे रेत के अवैध उत्खनन मामले पर पटवारी को भी जानकारी नहीं होना समझ से परे है जब नाले से हो रहे अवैध उत्खनन की जानकारी जब आम आदमी को है तो फिर राजस्व विभाग के पटवारी को क्यों नहीं..? ऐसे कई सवाल ग्राम में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मोक्ष धाम स्थित राजस्व नाले से भारी मात्रा में रेत निकाली जा रही है, राजस्व और खनिज विभाग को चाहिए कि वह घईलीजोड़ी नाले से हो रहे सुबह और शाम अवैध रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन पर अंकुश लगाए और खनिज संपदा की चोरी करने वालों पर चोरी का मामला दर्ज किया जाए जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहेगा!.

प्रेस क्लब अध्यक्ष नारायण सोमानी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर नीमच दशहरा मैंदान में सर्व हिंदू समाज द्वारा विराट धरना-प्रदर्शन एवं आक्रोश रैली में हुए शामिल, हिंदूवादी नेता सोमानी ने विरोध दर्ज कराया

जावद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में बुधवार को सर्व हिंदू समाज द्वारा जावद नगर भी प्रातः से दोपहर तक पूर्णरूप से बंद रहा। प्रेस क्लब अध्यक्ष एवं हिंदूवादी नेता नारायण सोमानी सहित नगरवासी 4 दिसम्बर 2024 बुधवार को नीमच स्थित दशहरा मैदान से सर्व हिंदू समाज द्वारा विराट धरना-प्रदर्शन, एवं आक्रोश रैली में शामिल हुए। जावद कृषि मंडी से दोपहर 12 बजे सभी हिंदू भाई एकत्रित होकर अपने अपने फोर व्हिलर, टू व्हिलर निजी वाहनो से जय-जय सियाराम, भारत माता के जयघोष के साथ नीमच दशहरा मैदान पर आयोजित विराट धरना-प्रदर्शन, एवं आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए रवाना हुए। अध्यक्ष एवं हिंदूवादी नेता नारायण सोमानी, वरिष्ठ मदनलाल वीरवाल जैन, जिनेंद्र बागडिया, विजय तिवारी, संदीप बाफना, आचार्य बुद्धिप्रकाश व्यास, पुरण चंदेल, रमेश शर्मा, राकेश सेन, हर्ष शर्मा, सुनील काबरा, मयंक पाटीदार, सौरभ शर्मा, आयुष शर्मा सहित नगरवासी नीमच पहुंचकर हिंदू भाईयों सनातन धर्म की रक्षा एवं बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार को रोकने हेतू सर्व समाज का विराट धरना-प्रदर्शन एवं आक्रोश रैली में शामिल होकर विरोध दर्ज किया।

सनातन पर प्रहार के विरोध में उमड़ा जन सैलाब

बांग्लादेश के खिलाफ मुखर हुआ दमोह

दमोह - बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के प्रभुजी चिन्मयानंद को आंतकवादी घोषित कर जेल में ठूंसे जाने के विरोध में दमोह में सनातनियों का सैलाब स्थानीय तहसील ग्राउंड में उमड़ा जिसमें नर से लेकर नारी, संत से लेकर मंत्री, आम से लेकर खास ने अपनी उपस्थिती दर्ज कराते हुए यह ऐहसास कराया कि अब सनातन की रक्षा के लिए हम सब एक है और मुखर हैं। जिसका नजारा तहसील ग्राउंड मंच से नजर भी आया। प्रमुख वक्ताओं ने बांग्लादेश के लिए भर्त्सना वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। संपूर्ण समाज के बीच में मंच पर अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जैन अटल, सुप्रसिद्ध कथा वाचिका सुश्री किशोरी वैष्णवी जी सनातन चेतना मंच के संयोजक दिनेश चौबे मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोग रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे।

सन्यासी को बना दिया आतंकवादी

सनातनी आग बबूला इसलिए हो गए कि इस्कॉन मंदिर का प्रत्येक सन्यासी जिन्हें प्रभुजी के नाम से जाना जाता है, वह हरे कृष्ण, हरे राम नाम जप की 16 माला नियमित करते हैं। भगवन नाम जप में लीन रहने वाले सन्यासी ने वहां हो रहे कत्ले आम का विरोध किया तो वह कि कटटरपंथी सरकार ने सन्यासी को आंतकवादी घोषित कर जेल में ठूंस दिया। उनकी जमानत के लिए जो वकील तैयार हो रहे हैं, उन्हें कटटरपंथी मौत के घाट उतार रहे हैं, जिसका विरोध सनातन चेतना मंच के बैनर तले किया गया।

बैठे हैं चंद्रमुखी, खड़े हैं तो ज्वालमुखी

मुख्यवक्ता सिद्धेश्वरी काली मठ पुरनहाउ धाम के पीठाधीश्वर रंजितानंद जी महाराज ने बांग्लादेश में साधु संतों के खिलाफ अत्याचार को लेकर कहा कि वह हमारे टुकड़ों पर पलने वाला बांग्लादेश आज आंख दिखा रहा है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि हिंदू समाज सब की कल्याण की भावना करने वाला समाज है। यदि संपूर्ण विश्व की कल्याण की कामना जीव के कल्याण के लिए सनातन समाज काम करना जानता है, तो राक्षसों और दुष्टों को कीड़े मकोड़े की तरह मसलना भी जानता है। हमारा इतिहास दान बलिदान कल्याण कर रहा है, तो हमने बड़े-बड़े राक्षसों का संहार भी किया है। जब तक हम बैठे हैं तो चंद्रमुखी हैं जिस दिन खड़े हो गए तो ज्वालामुखी बन जाएंगे। हिंदू को अब बैठना नहीं है हिंदू को अब खड़े होना है।

252 अल्पसंख्यक अधिकारी बर्खास्त

इस विशाल विरोध प्रदर्शन के संयोजक दिनेश चौबे ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। वहां लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है। 252 अल्पसंख्यक अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है, उनके परिजनों के साथ घटनाएं हो रही हैं। यह बात किसी से नहीं छपी। जिस भारत ने मुक्ति वाहिनी के माध्यम से बांग्लादेश को आजादी दिलाई आज वह कहता है कि हम अपने आप आजाद हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को **मिलकर अपने अल्पसंख्यक भाइयों की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए।**

इनकी रही मौजूदगी संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अलावा जिला पंचायत सदस्य पार्षद गण समाज के सामान्य नागरिक बनकर इस महाविरोध में सम्मिलित हुए। इसके अलावा जिले के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग के लोग डॉक्टर एडवोकेट व्यापारिक व्यवसाय उद्योगपति सभी पैदल मार्च करते हुए बांग्लादेश के विरोध में सडकों पर एकजुट दिखे। एकत्रीकरण स्थल तहसील ग्राउंड से पैदल मार्च करते हुए सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां पहुंचकर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को ज्ञापन दिया ज्ञापन का वचन कार्यक्रम के संयोजक दिनेश चौबे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम संचालन सहसंयोजक मोंटी रैकवार के द्वारा, अतिथि वक्ताओं का स्वागत सहसंयोजिका एडवोकेट गिरिजा त्रिपाठी एवं प्रमोद विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। आभार पवन रजक के द्वारा किया गया।

24 घंटे का रामधुन संगीतमय सीताराम नाम का किया गया जाप और संगीतमय सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन

दमोह-विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता व ग्रामवासी द्वारा ग्राम जुझार के राधा कृष्ण मंदिर में साप्ताहिक मंगल एवं सप्ताहिक रामायण पाठ के उद्यापन में 24 घंटे का रामधुन संगीतमय सीताराम नाम का जाप किया गया और संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ एवं विधि विधान से पूजा अर्चन हवन पूजन कर हवन में पूर्ण आहुति के साथ संपन्न किया गया इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयोजक कड़ोरी सेन ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण को लेकर रामायण पाठ प्रारंभ किया गया था जिसमें यह साप्ताहिक रामायण पाठ चल रहा था और मंदिर का निर्माण भी हो गया है आज 4 वर्ष पूर्ण होने पर रामायण पाठ का उद्यापन कर समापन किया गया इस प्रकार के कार्य निरंतर संगीतमय सुंदरकांड पाठ,रामायण पाठ चलते रहेंगे और समस्त क्षेत्रवासी एवं जिलेवासी से अनुरोध है इस प्रकार के कार्य करते रहे एवं सनातन धर्म की रक्षा और गौ माता कि रक्षा करना हमारा धर्म है एवं कन्या भोज और भव्य गक्कड़ भर्ता का भंडारा आयोजित हुआ इस अवसर पर पंडित तेजेंद्र तिवारी, पंडित द्वारका प्रसाद तिवारी,भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरिश्चंद्र पटेल, विकास नामदेव,भीम पटेल, पंडित राम गौतम, पंडित शंकर गौतम, पंडित अंशु दुबे, पंडित अरविंद पाठक, ग्राम पंचायत रियाना जुझार सरपंच दर्शन सिंह लोधी,मुड़ारी सरपंच मुकेश सिंह लोधी, ग्राम पंचायत रियाना जुझार रोजगार सहायक सचिव लोकेंद्र तिवारी ,शिक्षक कैलाश असाटी, शिक्षक अनिल मिश्रा, वाटर एड संस्था से आशीष ठाकुर, प्रतिभा चौरसिया, सौरभ सिंह लोधी, नीतेश सिंह लोधी,पन्नालाल असाटी, मयूर असाटी, कडोरी सेन, परम विश्वकर्मा, शुभम असाटी,कैलाश आदिवासी, हेमेंद्र असाटी राजन,हल्के सेन, छोटे लाल अठया, रामकुमार सेन ,धनीराम अठया, पप्पू सिंह ठाकुर, प्रेम सेन, अतुल सेन, जुगराज महोबिया, खिलान महोबिया, ऋषभ जैन,भागीरथ ठाकुर,देवेंद्र विश्वकर्मा,रामजी महोबिया, पारस विश्वकर्मा, विजय अठया ,नेहाल सेन, नीरज महोबिया ,सहित समस्त विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता व ग्रामवासी की उपस्थिति रही।

अब कॉलेज में सिखाया जाएगा रोमांस! इस देश ने आखिर क्यों शुरू की लव एजुकेशन

इंटरनेशनल डेस्क. चीन में घटती जन्म दर एक गंभीर समस्या बन चुकी है, और इसे लेकर सरकार चिंतित है। इस समस्या के समाधान के लिए चीनी सरकार अब एक नया कदम उठाने जा रही है। सरकार कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में लव एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने का विचार कर रही है, जिससे विवाह, प्रेम और पारिवारिक जीवन को लेकर युवाओं की सोच में बदलाव लाया जा सके। सरकार को उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से समाज में विवाह और बच्चों के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा।

घटती जनसंख्या की वजह से परेशानी

यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब चीन लगातार दूसरे साल जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और कम होती कार्यशील जनसंख्या की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था और सरकारी संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। चीन की आबादी लगभग 1.4 बिलियन यानी 140 करोड़ है, लेकिन इसके बावजूद यहां बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

सरकार का मानना है कि कॉलेज के छात्र, जो भविष्य में देश की जनसंख्या में योगदान देंगे, उन्हें विवाह और परिवार के बारे में सोचने और समझने की जरूरत है।

युवाओं की सोच में बदलाव लाने की कोशिश

हाल ही में एक सर्वे में यह सामने आया कि लगभग 57% कॉलेज के छात्र रोमांटिक रिश्तों में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि वे अपनी शिक्षा और व्यक्तिगत रिश्तों को संतुलित नहीं कर पाते, जिसके चलते वे ऐसे रिश्तों से दूर रहते हैं।

इसलिए, सरकार का मानना है कि विश्वविद्यालयों में विवाह और लव एजुकेशन पर जोर देने से युवा पीढ़ी में रिश्तों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो सकती है। सरकार का उद्देश्य विवाह और बच्चों के जन्म को लेकर एक अच्छा सांस्कृतिक माहौल बनाना है। अब यह देखना होगा कि सरकार का यह प्रयास युवाओं की सोच में बदलाव ला पाता है या नहीं, और क्या इससे जनसंख्या वृद्धि में कोई सुधार होता है।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर नहीं थम रहे हमल

सुनामगंज में भीड़ ने की दुकानों-घरों में तोड़फोड़

ढाका: बंगलादेश में हिंदू समुदाय पर एक और लक्षित हमले में हुए हैं। सुनामगंज जिले के दोवाराबाजार इलाके में भीड़ ने मंगलवार को हिंदुओं की कई दुकानों और घरों को लूट लिया और तोड़फोड़ की। कथित तौर पर एक स्थानीय हिंदू युवक द्वारा फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के बाद यह हमला हुआ। हमले शाम से आधी रात के बीच हुए। बिजनेस स्टैंडर्ड बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, बंगलादेश की सेना ने 2:30 बजे तक स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। दोवाराबाजार के थाना प्रभारी जहीदुल हक ने कहा कि पोस्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने कहा, हम हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों ने कहा कि कथित आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर एक समूह ने जुलूस निकाला और इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के घरों और दुकानों पर हमला किया। वहीं, अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के नेताओं ने कहा कि उनके कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। बंगलादेश की सरकार ने इस घटना को कमतर आंका है।

दोवाराबाजार लोकनाथ मंदिर प्रबंधन समिति के महासचिव खोकन रॉय ने कहा, मंगलवार रात गांव के कम से कम 30 घरों में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद हमलावरों ने स्थानीय रसोई बाजार क्षेत्र में जुलूस निकाला और 100 से अधिक दुकानों में तोड़फोड़ की। उन्होंने 4-5 स्वर्ण दुकानों में भी लूटपाट की। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने लोकनाथ मंदिर में तोड़फोड़ की, जिससे 20 लाख टका (16,725.57 डॉलर) तक का नुकसान हुआ।

खोकन ने आरोप लगाया कि स्थानीय बंगलादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के नेता गौर दास के घर और पारिवारिक मंदिर पर हमला किया गया। स्थानीय प्रशासन ने हालांकि इस घटना को कमतर आंकते हुए अतिरंजित आंकड़ों का दावा किया और कहा कि हमला बड़ा नहीं था और केवल कुछ प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा है। दोवाराबाजार उपजिला निर्वाही अधिकारी (यूएनओ) मेहर निगार टोनू ने कहा, कुछ घरों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई, लेकिन हमें अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि कितने घरों पर हमला किया गया। स्थिति अब नियंत्रण में है। सुनामगंज के उपायुक्त मोहम्मद इलियास मिया ने कहा, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। एक निहित स्वार्थी वर्ग जानबूझकर घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। यह इलाका अब स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण में है। गौरतलब है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सेना समर्थित अंतरिम सरकार के तहत हिंदू समुदाय पर हमलों में काफी वृद्धि देखने को मिली है। भीड़ द्वारा हिंसा और बर्बरता की कई घटनाएं सामने आई हैं, और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अपराधियों के खिलाफ काफी हद तक उदासीन प्रतिक्रिया दी गई है। भारत ने बंगलादेश की सरकार से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।

लाहौर में दमघोंटू धुंध का प्रकोप

प्रदूषण स्तर खतरनाक ऊंचाई पर

इंटरनेशनल डेस्क। कभी गार्डन सिटी के नाम से मशहूर लाहौर अब दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गया है। मंगलवार को, डीएचए फेज़-5 और अमेरिकी दूतावास के आसपास के क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) क्रमशः 459 और 433 तक पहुंच गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, यह संकट न केवल प्रशासन की नाकामी को उजागर करता है बल्कि लाखों लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा भी बन चुका है।

प्रदूषण के कारण

लाहौर में बढ़ते प्रदूषण के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें शामिल हैं जैसे औद्योगिक उत्सर्जन के तहत फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना रहा है। वाहन प्रदूषण में पुराने और खराब इंजन वाले वाहनों का उपयोग। और आसपास के इलाकों में पराली जलाने से हवा में जहरीले कण बढ़ रहे हैं।

सरकार की कोशिशें और नाकामी

पंजाब सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे खराब इंजन वाले वाहनों के रूट परमिट रद्द करना। ईंट भट्टों और तीन औद्योगिक इकाइयों को सील करना। भारी वाहनों पर प्रतिबंध और सड़कों पर पानी का छिड़काव। हालांकि, ये कदम इस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। 1,000 से अधिक वाहनों की जांच के बाद केवल 144 को जब्त किया गया।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने निकट भविष्य में बारिश की संभावना से इनकार किया है, जिससे प्रदूषण की स्थिति और खराब हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि लाहौर में हवा की गति केवल 6 किमी/घंटा है और 81% तक नमी का स्तर स्थिति को और बदतर बना रहा है। अस्पतालों में सांस की बीमारियों के मरीजों की बाढ़ आ गई है। सीनियर मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मॉग को खत्म करने में आठ से दस साल लगेंगे। उनके इस बयान की आलोचना हुई है, क्योंकि यह समस्या की तात्कालिकता को नकारता है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन विज्ञान आधारित त्वरित समाधान देने में विफल रहा है।

डॉन ने दी चेतावनी

लाहौर का यह संकट पाकिस्तान की खराब पर्यावरण नीति और प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाता है। अगर तुरंत प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो लाहौर स्थायी रूप से इस संकट का शिकार हो सकता है। डॉन ने चेतावनी दी है कि बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रभावी नीति के, यह शहर पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण बन जाएगा। लोगों को जहरीली हवा में जीने को मजबूर करने वाली इस स्थिति ने प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया है। लाहौर की हवा साफ करने के लिए मजबूत नीतियां और दृढ़ इच्छाशक्ति की तत्काल आवश्यकता है।

यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे का बड़ा कदम

10,000 सामान्य कोच तैयार किए जा रहे हैं - वैष्णव

नॅशनल डेस्क। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में भारतीय रेलवे के सुधारों को लेकर कुछ अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि रेलवे आम यात्रियों को अधिक सहूलियत देने के लिए अपनी ट्रेनें और सेवाएं सुधारने पर जोर दे रहा है। इसके तहत रेलवे जल्द ही अपने बेड़े में 10,000 सामान्य कोच जोड़ने की योजना बना रहा है जिनमें से पहले 1,000 कोच दिसंबर 2024 तक जोड़े जाएंगे। यह कदम खासकर उन यात्रियों के लिए उठाया जा रहा है जो एसी कोच की बजाय सामान्य डिब्बों में यात्रा करना पसंद करते हैं।

रेलवे संशोधन विधेयक पेश

लोकसभा में बुधवार को अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है और रेलवे के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। उनके मुताबिक भारतीय रेलवे पुनर्विकास परियोजना के तहत 1,300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है जो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे पुनर्निर्माण परियोजना मानी जा रही है।

रेल मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के तहत कई स्टेशनों का पुनर्निर्माण 700-800 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा जबकि कुछ अन्य स्टेशनों का पुनर्निर्माण 100-200 करोड़ रुपये की लागत से होगा। इसके अलावा रेलवे के नेटवर्क के विस्तार, पटरियों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि

तकनीक का इस्तेमाल करने से रेल दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है।

महिलाओं की बढ़ी संख्या

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि रेलवे में महिला कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2024 तक 99,809 हो जाएगी। इनमें से 2,037 महिलाएं लोको पायलट हैं जो रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

टिकटों पर छूट

विपक्ष ने बुजुर्गों और अन्य वर्गों को मिलने वाली सब्सिडी फिर से शुरू करने की मांग की थी जिस पर वैष्णव ने जवाब देते हुए बताया कि रेलवे हर साल 56,993 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है। इसके तहत हर टिकट पर 46 प्रतिशत की छूट दी जाती है। उदाहरण के लिए अगर टिकट की कीमत 100 रुपये है तो रेलवे केवल 54 रुपये ही लेता है। यह सब्सिडी भविष्य में भी जारी रहेगी।

रेलवे बोर्ड का एकीकरण

वहीं रेल मंत्री ने बताया कि सरकार रेलवे अधिनियम 1989 और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को एकीकृत करने की दिशा में काम कर रही है। इस प्रस्तावित रेलवे संशोधन विधेयक के तहत रेलवे बोर्ड अधिनियम को निरस्त किया जाएगा और इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम में शामिल किया जाएगा।

वैष्णव ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य रेलवे का निजीकरण नहीं है बल्कि उसका आधुनिकीकरण करना है। उन्होंने कहा कि रेलवे की शुरुआत लोकनिर्माण विभाग के अंग के रूप में हुई थी लेकिन अब यह देश की यातायात का मुख्य हिस्सा बन चुका है। इस सुधार का उद्देश्य रेलवे की कार्यक्षमता बढ़ाना है।

विपक्ष का विरोध

विपक्ष ने इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि सरकार रेलवे का निजीकरण कर रही है जिससे युवाओं के रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। विपक्ष का कहना था कि सरकार आधुनिकीकरण के नाम पर रेलवे को निजी हाथों में बेच रही है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने वंदे भारत ट्रेनों में परोसे जाने वाले खराब भोजन का मुद्दा उठाया और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन में कीड़े पाए जाने की घटनाओं का उदाहरण भी दिया।

रूस ने भूमध्य सागर में दागी हाइपरसोनिक मिसाइलें, सैन्य अभ्यास में दिखाया दम

रूस ने अपनी अत्याधुनिक सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए भूमध्य सागर में **जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें** सफलतापूर्वक दागी। यह मिसाइलें रूसी नौसेना के एडमिरल गोर्शकोव और एडमिरल गोलोवको युद्धपोतों से लॉन्च की गईं और अपने निर्धारित लक्ष्यों को सटीकता से भेदने में कामयाब रहीं। इस व्यापक सैन्य अभ्यास का नेतृत्व रूस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसियेव ने किया। अभ्यास में 1,000 से अधिक सैन्यकर्मी, 10 युद्धपोत, 24 विमान और उन्नत उच्च-सटीक हथियार शामिल थे।

इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और रूस की उन्नत सैन्य तकनीकों का परीक्षण करना था। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से कई गुना तेज हैं और इन्हें रोकना लगभग असंभव माना जाता है। इनकी गति और सटीकता इन्हें आधुनिक युद्ध में बेहद प्रभावी बनाती हैं। यह सैन्य अभ्यास भूमध्य सागर में रूस की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को रेखांकित करता है। रूस ने अपनी उच्च-प्रौद्योगिकी और सैन्य तैयारी का प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। यह अभ्यास वैश्विक सुरक्षा और सैन्य संतुलन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे समय में जब रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है।

अमेरिका ने ईरान की तेल परिवहन वाली 35 कंपनियों और जहाजों पर लगाए प्रतिबंध

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका ने ईरान के तेल का अन्य देशों में परिवहन करने वाली 35 कंपनियों और जहाजों पर मंगलवार को प्रतिबंध लगा दिया। इनमें भारत की दो कंपनियां भी शामिल हैं। भारत की जिन दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें 'फोनिक्स का प्रबंधन और संचालन करने वाली 'विजन शिप मैनेजमेंट एलएलपी और 'टाइटशिप शिपिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, लाइबेरिया, हांगकांग सहित अन्य देशों की कंपनियों और जहाजों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक बयान में, वित्त विभाग ने कहा कि एक अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले के बाद की गई यह कार्रवाई तेहरान पर एक और चोट है। ईरान ने 11 अक्टूबर को लगाए गए प्रतिबंधों के बाद परमाणु कार्यक्रमों को तेज करने की घोषणा की है।

आतंकवाद और वित्तीय खुफिया विभाग के कार्यवाहक अवर सचिव ब्रैडली टी स्मिथ ने कहा, ''ईरान अपने पेट्रोलियम व्यापार से होने वाले राजस्व को परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के प्रसार तथा आतंकवादियों पर खर्च कर रहा है, जिससे क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता पैदा होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सभी संसाधनों और प्राधिकारों का इस्तेमाल कर इन अवैध गतिविधियों को सरंक्षण देने वाले जहाजों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569